कोविड-19
पर विशेष अंक

खंड ३ | नंबर १ | मार्च-मई २०२०

विकास सहयोग समीक्षा

(डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिव्यू)

संपादकीय

विशेष लेख

कोविड–19: महामारी और अफ्रीका
अमर सिन्हा

अफ्रीका में कोविड–19 और विकास की गतिशीलता
जॉन पैट्रिक

कोविड–19: अफ्रीका के लिए अभूतपूर्व चुनौती
महेश सी. अरोड़ा

कोविड–19 और नई भू–राजनीति
प्रत्यूष शर्मा

(शेष बाहर के पिछले कवर पर जारी)

विकास सहयोग समीक्षा

सम्पादक

सचिन चतुर्वेदी — महानिदेशक, आरआईएस

अमर सिन्हा — विशिष्ट फेलो, आरआईएस

प्रबंध सम्पादक

मिलिन्दो चक्रबर्ती — विजिटिंग फेलो, आरआईएस

सहयोगी सम्पादक

प्रत्यूष शर्मा — संवाददाता ,डीसीआर

सम्य सहायक

अदिती गुप्ता — रिसर्च असिस्टेंट, आरआईएस

सम्य सलाहकार मंडल

मोहन कुमार — चेयरमैन, आरआईएस

जॉर्ज चेडिक — डॉयरेक्टर, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ–साउथ कोऑपरेशन

ली शियाओयून — चेयर, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च नेटवर्क

अनुराधा शिनॉय — चेयरपर्सन, एफआईडीसी एवं पूर्व डीन, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय

एलिजाबेथ सिदिरोपोलस — चीफ एक्जीक्यूटिव, साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स

राजेश टंडन — फाउंडर, पार्टिसपेटॉरी रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए)

आंद्रे डि मेलोय सूज़ा — सीनियर रिसर्च फेलो, इंस्टीट्यूटो डि पेस्क्वीज़ इकॉनोमिका एप्लीकेडा (आईपीईए)

गुलशन सचदेवा — ज्यां मोने चेयर एवं डायरेक्टर, यूरोप एरिया स्टडीज़ प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय

थॉमस फ्यूज़ — पूर्व प्रमुख, मैनेजिंग ग्लोबल गवर्नेंस प्रोग्राम एट जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट

रुचिता बेरी — सीनियर रिसर्च एसोसिएट, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिज

फिलानी मथेम्बु — एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डायलॉग

अमिताभ बेहर — चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑक्सफेम इंडिया

सिरिपोर्न वज्जवाल्कु — एसोसिएट प्रोफेसर, पोलिटिकल साइंस, थाम्मासात यूनिवर्सिटी, बैंकॉक, थाईलैंड

हर्ष वी. पंत — विशिष्ट फेलो एवं हैड, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम, ओआरएफ

मुस्ताफिजुर रहमान — विशिष्ट फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग

कौस्तुव कांति बंदोपाध्याय — डायरेक्टर, सोसायटी फॉर पार्टिसपेटॉरी रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए)

बिष्वम्भर पयाकुर्याy — श्रीलंका और मालदीव में नेपाल के राजदूत

श्रीराम चौलिया — प्रोफेसर, एवं डीन, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स

दुश्नी वीराकून — एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं हैड, मैक्रोइकॉनोमिक्स पॉलिसी रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज़

स्वर्ण सिंह — प्रोफेसर, डिप्लोमेसी एंड डिसार्ममेंट, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय

हर्श जेटली — चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, वालन्टेरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वीएएनआई)

कोविड-19
पर विशेष अंक

विकास सहयोग समीक्षा

खंड ३ | नंबर १ | मार्च-मई २०२०

विकास सहयोग समीक्षा

खंड ३ नंबर १ मार्च-मई २०२०

संपादकीय 1

विशेष लेख 3

कोविड–19: महामारी और अफ्रीका
अमर सिन्हा

अफ्रीका में कोविड–19 और विकास की गतिशीलता 7
जॉन पैट्रिक

कोविड–19: अफ्रीका के लिए अभूतपूर्व चुनौती 12
महेश सी. अरोड़ा

कोविड–19 और नई भू–राजनीति 17
प्रत्यूष शर्मा

भारत–अफ्रीका संबंध: वर्तमान संकट और भविष्य 23
अभिनव झा

कोविड–19 और अफ्रीका के सामने चुनौती 27
अदिति गुप्ता

परिप्रेक्ष्य

विकास सहयोग की भाषा और स्वरूप 31

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता: वर्तमान महामारी से सबक
मिलिन्दो चक्रवर्ती

संपादकीय

विकास सहयोग समीक्षा (डीसीआर) की संपादकीय टीम की ओर से पाठकों का अभिनंदन। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके निरंतर संरक्षण और समर्थन के परिणामस्वरूप *डीसीआर* का प्रकाशन अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसे और आकर्षक बनाने के लिए, विकास सहयोग से संबंधित अधिक विश्लेषणात्मक आलेखों, जो आगे की चुनौतियों के बारे में पाठकों को एक निर्णायक दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक होंगे, के साथ पत्रिका को समृद्ध करने का निर्णय लिया गया है। बेहतर के लिए बदलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष से *डीसीआर* का प्रकाशन त्रैमासिक होगा अर्थात इसे वर्ष में चार बार प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकाशन के अधिकतर अंक कुछ विशिष्ट और प्रासंगिक मुद्दों पर केंद्रित होंगे। वर्तमान अंक उस वैश्विक महामारी के संबंध में विकास सहयोग के लिए चुनौतियों पर केंद्रित है जिसकी मार पूरी दुनिया झेल रही है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के रूप में 190 से अधिक देशों में फैल गया है। नतीजा यह है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को आय का स्तर गिरने, बेरोजगारी बढ़ने, उपभोक्ता मांग में गिरावट, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने और सिकुड़ते निर्यात राजस्व तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन आदि जैसी दुनिया की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त होने के कगार पर हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका, जहां बेरोजगारी दर 14.7 प्रतिशत तक बढ़ गई है, महामंदी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वैश्विक दक्षिण के देश भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। युद्धस्तर पर लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना देशों के बीच विकास सहयोग का तात्कालिक लक्ष्य होगा।

डीसीआर का वर्तमान अंक अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड–19 के प्रभाव और अफ्रीकी राष्ट्रों द्वारा इस चुनौती से प्रभावी ढंग से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर केंद्रित है। । अब तक 2000 से अधिक मौतों के साथ अफ्रीकी महाद्वीप में कोविड–19 के 60,000 से अधिक पुष्ट मामले सामने आए हैं। हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड के कारण अफ्रीका में 1,90,000 लोगों की मृत्यु हो सकती है और यदि इसकी रोकथाम के उपाय विफल होते हैं तो 29 से 44 मिलियन लोगों पर इस बीमारी का खतरा है।

दुनिया में सबसे गरीब महाद्वीप होने के नाते, अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पहले से ही बहुत कम डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों तथा सीमित महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयों आदि के रूप में विभिन्न कमियों से ग्रस्त है, अधिकांश अफ्रीकी देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बहुत उन्नत करने की आवश्यकता है।

चूंकि कई अफ्रीकी देशों में एचआईवी, तपेदिक, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों का अत्यधिक प्रचलन है, इसलिए अधिक संभावना है कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त आबादी में मृत्यु दर काफी ज्यादा हो सकती है। । इसे कम करने के लिए, प्रति व्यक्ति अस्पताल के बेड, महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयों, वेंटिलेटर, आदि पर सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि करने की आवश्यकता है। सरकारों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इससे ग्रस्त लोगों की पहचान कर उन्हें बाकियों से अलग रखने के लिए परीक्षण और पहचान करने की प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भरोसेमंद दवा आपूर्ति श्रृंखला बनाने और जैव–प्रौद्योगिकी में घरेलू क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल देने के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तकनीक का अधिक उपयोग आवश्यक है। मोबाइल भुगतान प्रणाली, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म आदि, भीड़भाड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करते हैं। कई राष्ट्रीय सरकारों ने लोगों को महामारी के बारे में जानकारी प्रसारित करने और निवारक उपाय करने में मदद करने के लिए विभिन्न वेब आधारित ऐप भी पेश किए हैं।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी अफ्रीकी देशों में भंडारण और वितरण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की आवश्यकता है। खेतों के मशीनीकरण स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए और आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी अपव्यय को कम किया जाना चाहिए।

सरकारों को एक मूल आय सहायता निधि के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें सभी देशों को योगदान करना चाहिए और जिसका उपयोग आगे की महामारियों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह के समर्थन कोष विभिन्न देशों के क्षेत्रीय समूहों द्वारा भी बनाए जाने चाहिए।

यह अनुमान लगाया गया है कि अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफसीएफटीए) 2030 तक उपभोक्ता खर्च में 1.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि करेगा। अफ्रीकी आर्थिक आकलन 2019 के अनुसार, अफ्रीका प्रत्येक वर्ष लगभग 134 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त कर सकता है, यदि अन्य विकासशील देश अपने टैरिफ व गैर टैरिफ बाधाओं को पचास प्रतिशत कम कर देते हैं। अफ्रीकी देशों को घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने और व्यवसायों की मदद करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए अतिरिक्त राजकोषीय राजस्व प्रदान करने के लिए एएफसीएफटीए के कार्यान्वयन में तेजी लाई जानी चाहिए।

डीसीआर का वर्तमान अंक मुद्दा अपने नए प्रारूप में, इन प्रमुख चिंताओं में से कईयों को छूता है। आपका योगदान शोध आलेखों, टिप्पणियों तथा जमीन से भेजी गई रिपोर्टों के माध्यम से इस प्रकाशन के आगामी अंकों को सार्थक तरीके से समृद्ध करेगा।

कोविड–19 महामारी और अफ्रीका

*अमर सिन्हा**

''इस संकट का असर प्रत्येक देश की क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है और नैतिक दुविधा पैदा कर रहा है कि जीवन बचाया जाए यां आजीविका !''

कोविड–19 महामारी, जो वुहान चीन के एक पशु–बाजार में शुरू हुई, ने किसी भी देश को नहीं बख्शा, हालांकि राष्ट्रों में इसके प्रसार और गंभीरता में उल्लेखनीय अंतर देखा जा रहा है। जबकि अफ्रीका में संक्रमण की सबसे अधिक संख्या मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया द्वारा बताई गई है, उप–सहारा अफ्रीका में ये संख्या तीन अंकों या उससे कम है। अफ्रीका अपनी युवा आबादी के साथ अधिक पुरानी और बढ़ती आबादी वाले समाजों के रूप में बुरी तरह से प्रभावित नहीं हो सकता है, फिर भी इसके आर्थिक प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। अफ्रीका में इसके प्रसार की धीमी गति ने सही नीतियों को लागू करने और दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया है। हालाँकि, इस अदृश्य शत्रु से खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, और एक अभी भी 2020 की दूसरी तिमाही में महामारी फैलने में एक बड़ा उछाल देख सकता है। यह स्पष्ट है कि तीन महीने पहले इसके शुरूआती मामलों की जानकारी मिलने के बाद इससे प्रभावित मामलों की संख्या विभिन्न देशों में अलग–अलग समय पर चरम पर पहुंची है।

इस महामारी का असर मानवीय जीवन पर प्रत्यक्ष तो होता ही है साथ ही आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भी लोग प्रभावित होते हैं। सरकार किस प्रकार से इससे निपटती है, उसी के आधार पर उसे एक राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।

इस रोग का इलाज यां कोई वैक्सीन निकट भविष्य में उपलब्ध होने की आशा ज्यादा नहीं है। ऐसे में सरकारों ने पूर्व में परिणाम देने वाले कदम उठाए हैं मसलन लॉकडाउन करना तथा शारीरिक दूरी बनाए रखने पर जोर देना।

*विशिष्ट फेलो, आरआईएस, ये व्यक्तिगत विचार हैं।

सरकारों को उम्मीद है कि इससे रोग से प्रभावित होने वालों की संख्या में वृद्धि कम होती जाएगी, बीमारी का फैलाव देर से होगा तथा सीमित संसाधनों वाले स्वास्थ्य क्षेत्र को रोगियों की बड़ी संख्या के बोझ के तले ढह जाने से बचाया जा सकेगा। विकसित देशों में भी स्वासथ्य सेवाएं इस महामारी के प्रभाव को झेल नहीं पा रही हैं। इस संकट का असर प्रत्येक देश की क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है और नैतिक दुविधा पैदा कर रहा है कि जीवन बचाया जाए यां आजीविका !

आईएमएफ ने अफ्रीका के जीडीपी में अधिकतम सिकुड़न का आकलन किया है। यह सिकुड़न लगभग 1.6 प्रतिशत के आसपास होगी। लेकिन साथ ही आईएमएफ ने यह सकारात्मक आकलन भी किया है कि अफ्रीका अपनी स्थिति में वापस पहले जैसी स्थिति में जल्दी पहुंच सकता है। यह बात सही है कि कई अफ्रीकी देश बड़ी तेजी से आर्थिक विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे थे जबकि कुछ ऐसे देश भी थे जिनमें की आर्थिक विकास बहुत धीमा था और कर्ज बहुत ज्यादा। अब ऐसे देशों के पास कर्ज अदायगी करने का विकल्प आसान नहीं होगा। फिलहाल चुनौती यह है कि मौजूदा नुकसान को इस प्रकार से सीमित किया जाए ताकि भविष्य में यह अफ्रीकी विकास की गाथा को प्रभावित न कर सके। जिन देशों के आर्थिक क्षेत्रों में विविधता अधिक नहीं है और जो मूलतः पर्यटन, हॉस्पिटेलिटी, कृषि, तेल व गैस तथा अन्य खनिज पदार्थों पर निर्भर है उनके साथ दिक्कत ज्यादा हो सकती है।

द इकोनोमिस्ट ने लिखा है, ''अमीर देशों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं वह विकराल हैं पर उन समस्याओं के मुकाबले बहुत छोटी है जो गरीब देशों पर आने वाली है।'' यह आकलन काफी हद तक सटीक है। गौरतलब है कि एशिया और अफ्रीका के निर्धनतम देशों के सामने न केवल कमजोर और अपर्याप्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेक्टरों की चुनौती है बल्कि इसके अलावा उन्हें इस समस्या का सामना भी करना पड़रहा है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता सीमित है, आयात पर निर्भरता काफी अधिक है तथा जिन आयातित वस्तुओं की आवश्यकता है (जैसे कि दवाएं, टेस्टिंग किट पीपीई) उनके लिए भुगतान करने की उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। अगर उनके पास इसके लिए संसाधन हों तब भी दूसरे देशों के द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध उनकी जरूरत को पूरा करने में बड़ी बाधा साबित हो सकते हैं। यह प्रतिबंध इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ज्यादातर देश पहले खुद को बचाने की नीति–''पहले मै''–पर काम कर रहे हैं जिस पर कई सवाल हैं?

द इकोनोमिस्ट ने यह भी कहा है , ''इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की मदद करने के प्रयासों में भारी कमी महसूस की जा रही है।'' ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि जहां देशों ने अपने पास जो भी आपूर्ति थी उसे दबा कर रख लिया और दूसरे देशों को जा रही आपूर्ति की भी ज्यादा कीमत लगा कर उसे अपने देश की तरफ मोड़ लिया। यह भी स्पष्ट है कि घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताओं को और मजबूत करने के प्रयासों में काफी कमी है। इसके साथ ही इस बात का भी खतरा है कि झूठे आश्वासन देकर सामान बेचने के नाम पर कोई आप को बेवकूफ बना जाए अथवा जो समान आपको बेचा जाए वह उस गुणवत्ता का न हो जिस गुणवत्ता के लिए उसकी कीमत अदा की गई है। ऐसे कई मामले कई देशों में सामने आए हैं जिनमें भारत भी शामिल है।

भविष्य की राह

इस महामारी के कारण कई देश दोबारा अपनी नीतियों के बारे में सोचेंगे विशेषकर इन विषयों के संदर्भ में जिनमें भूराजनीतिक, बहुपक्षीय क्षेत्र तथा वैश्वीकरण की उपयोगिता रणनीतिक आत्मनिर्भरता की परिभाषा शामिल है इसके साथ ही इन विषयों पर भी पुनर्विचार होगा जिनमें की वह नियम कायदे शामिल हैं जिनके आधार पर विभिन्न देश एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। यह स्पष्ट मत बन रहा है कि वैश्विक संस्थान अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे हैं इसलिए उनकी भूमिका की भी बड़ी कड़ी समीक्षा होने वाली है। दुर्भाग्यवश ज्यादातर देशों की दूसरे देशों को मदद करने की क्षमता इस समय सीमित हो गई है क्योंकि वह घरेलू स्तर पर ही इस चुनौती से निपटने में लगे हुए हैं ऐसे में हो सकता है कि वह दूसरे देशों को अपने दूसरे देशों को मदद करने के लिए उस तरह से तैयार ना हो ऐसी की आवश्यकता है।

संकट के लिए सहयोग और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता होती है, लेकिन भूराजनीति के तर्क से लगता है कि बहुपक्षवाद प्रमुख रूप से हताहत होगा। इस चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि को देखते हुए, जहां अंतर्राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर होंगे, वहीं दक्षिणीय सहयोग के लिए तर्क मजबूत हो जाता है। विश्लेषकों ने हाल के दिनों से सबक लिया है, जब 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हुआ, आज की चुनौतियों में भी इसी प्रकार की सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। कोई भी राष्ट्र इस समस्या से अकेले नहीं निपट सकता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 'मूक प्रक्रिया 'के तहत सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया और अपनाया जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद' का आह्वान करता है।

भारत की भूमिका

भारत का हमेशा से सामूहिक कार्यवाही तथा सामूहिक समृद्धि में भरोसा रहा है। आजादी के बाद से भारतीय नीतियां इसी विश्वास से निर्देशित होती रही है। इसके कारण भारत नए ढांचे और ऐसे संस्थाएं बना पाया है जिनका फोकस दक्षिणीय सहयोग पर केंद्रित है तथा जिसमें विकसित देशों के अनुभवों को तथा दक्षिण की विशेषज्ञता को इस्तेमाल किया गया है। इस प्रयास को थिंक टैंक, सामाजिक संस्थाओं तथा समविचारी देशों द्वारा समर्थन की जरूरत है।

वैश्विक विकास केंद्र स्थापित करने में आरआईएस (आर्थिक, क्षेत्रीय एकीकरण और सतत विकास के मुद्दों में विशेषज्ञता वाला थिंक टैंक) द्वारा ग्लोबल डेवलेपमेंट सेंटर (जीडीसी) बनाकर एक प्रभावी पहल की गई है। यह मंच भारत के विकास के अनुभवों का लाभ उठाता है और इसे विकासशील देशों में ले जाने का प्रयास करता है और इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान का मंच बनाता है। इस पहल को यूके के डीएफआईडी का समर्थन मिला, जिसने भारत को ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए अग्रणी प्रदाता के रूप में मान्यता दी जो जमीन पर स्थानीय क्षमता का निर्माण करते हैं।

जबकि भारत सरकार चिकित्सा सहायता की आपूर्ति कर रही थी और जरूरतमंद देशों को बहुत अधिक मांग वाली दवाओं के शिपमेंट की सुविधा दे रही थी, आरआईएस/जीडीसी ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के साथ मिलकर कोविड–19

पर तीन वेबिनार आयोजित किए, जिसमें एशिया और अफ्रीका के 20 देशों के 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन वेबिनारों ने महामारी के हर पहलू पर ध्यान दिया– पहचान, परीक्षण, निदान, उपचार, आईसीयू देखभाल, अलगाव के साथ–साथ पेशेवरों के संरक्षण में स्वास्थ्य देखभाल। लॉक डाउन और यात्रा पर प्रतिबंध द्वारा लगाई गई सीमाओं का निदान नवाचार द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच इस पहल की लोकप्रियता प्रत्येक प्रस्तुति के बाद सक्रिय बातचीत में स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। यह केवल एक छोटा सा उदाहरण है कि महामारी के कारण भू–राजनीतिक स्तर पर व्यावहारिक और लागत प्रभावी सहयोग कैसे जारी रहेगा। भारत और उसके विभिन्न संस्थान हमारे मित्रों और पड़ोसियों की सहायता के मोर्चे पर मौजूद रहेंगे।

वैश्विक संकट के इस क्षण में एक–दूसरे के साथ खड़े होना समय की मांग है। भू–राजनीति को अभी इंतजार करना होगा ।

दक्षिण कोरिया व अफ्रीकी राष्ट्रों की कोविड–19 के खिलाफ संयुक्त जंग

कोविड–19 के कारण दक्षिण कोरिया और अफ्रीका के बीच सहयोग के नए अवसर सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया, जिसके व्यापक परीक्षण और संपर्क ट्रेसिंग के शासन की दुनिया भर में प्रशंसा की गई है, पहले से ही अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे–इन ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद के साथ बातचीत में अफ्रीकी राज्यों को सहायता प्रदान करने में जी –20 राज्यों के महत्व पर सहमति व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक, डा. टेड्रोस एडनोम घेबियस ने मून से अफ्रीकी देशों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चिकित्सा उपकरण और परीक्षण किट प्रदान करने का आग्रह किया था, जिसके लिए वह सहमत हो गए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले कोरोनावायरस प्रतिक्रिया कार्यक्रम में दक्षिण कोरिया के समर्थन का विस्तार करने का भी वादा किया है।

दक्षिण कोरिया और मोरक्को के विदेश मंत्रियों ने एक लेनदेन के लिए सहमति व्यक्त की जिसके तहत मोरक्को ने दक्षिण कोरियाई चिकित्सा आपूर्तिकर्ता से 100,000 परीक्षण किट खरीदी। दक्षिण अफ्रीका के साथ भी परीक्षण किटों की बिक्री से संबंधित ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार उनका देश अफ्रीका और मध्य पूर्व के 6 देशों में कोवडि19 की परीक्षण किट दान करने का इरादा रखता है।

सरकार के अलावा, दक्षिण कोरियाई गैर–लाभकारी संगठन भी अफ्रीकी देशों को सहायता प्रदान करने का नेतृत्व कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, इथियोपिया में, एक दक्षिण कोरियाई एनजीओ वार्मथ डे, मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) लाभार्थियों को उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा, अफ्रीका फ्रीडम फाउंडेशन और आन्यांग ग्लोबल मेथोडिस्ट चर्च नामक एक दक्षिण कोरियाई एनजीओ ने मेडागास्कर को 10 एम्बुलेंस दान में दी हैं ।

स्रोतः बोन, आर एंड किम, एम। (2020, 15 अप्रैल)। अफ्रीका में कोविड–19 में दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया। द डिप्लोमेट। https://thediplomat.com/2020/04/south-koreas-response-to- covid-19-in-africa /

अफ्रीका में कोविड–19 और विकास की गतिशीलता

*जॉन पैट्रिक**

''कोविड–19 के बाद के दौर में सभी प्रमुख ऋणदताओं की ओर से ऋणों के पुनर्गठन तथा ऋण माफी की आवश्यकता सभी दानदाताओं से होगी।''

कोविड–19 ने चीन के वुहान शहर में अपना भारी प्रकोप दिखाया। यह चीनी शहर मुख्य रूप से कोविड–19 की मार झेल रहा था। नतीजा यह हुआ कि लॉकडाउन के बाद चीन के उत्पादन केंद्र अचानक बंद हो गए। इससे अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के सामने एक अकल्पनीय परिदृश्य उपस्थित हो गया क्योंकि चीनी बाजार से वे बड़े पैमाने पर आयात भी कर रहे थे और निर्यात भी। इसके उपरांत वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं भी जैसे ठप्प हो गईं, विशेष रुप से यूरोप और उत्तर अमेरिका में, उससे स्थिति और भी बदतर हो गई। पर्यटन, तेल, गैस, व कृषि जैसे प्रमुख सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए। मैकेंजी एंड कंपनी ने 2020 के लिए यह अनुमान दिया है कि अगर स्थितियां बहुत बेहतर भी हो गई तब भी अफ्रीका का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सामान्य स्थितियों में 3.9 प्रतिशत से घटकर मात्र 0.4 प्रतिशत रह जाएगा। इस महाद्वीप में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से ही बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं जिनके कारण इस महामारी से निपटना अपने आप में और चुनौतीपूर्ण हो गया। निश्चित ही कोविड–19 से पैदा हुआ प्रभाव दीर्घकालीन है। यह आलेख कोविड–19 के अफ्रीका की विकास प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है।

कोविड–19: अफ्रीका में व्यापार, विनिर्माण और औद्योगीकरण पर प्रभाव

उप–सहारा अफ्रीका से मुख्य रूप से तेल, कच्चे माल और कृषि उत्पाद का 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर (विश्व बैंक 2018) का निर्यात होता है। चीन, अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। चीन में विनिर्माण क्षेत्र बंद होने से इस महाद्वीप के निर्यात के लिए बाजार में काफी

*रिसोर्स पर्सन,ग्लोबल डेवलेपमेंट सेंटर (जीडीसी), आरआईएस। ये व्यक्तिगत विचार हैं।

गिरावट आई। इसके अलावा, चीन में तालाबंदी ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को बाधित किया। अफ्रीका, चीन पर 60 प्रतिशत से अधिक आयात के लिए निर्भर है, जिसमें से ज्यादातर तैयार उपभोक्ता उत्पाद हैं और फिलहाल अफ्रीका इसकी भारी कमी का सामना कर रहा है।

लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह सामने आई है कि अन्य प्रमुख वैश्विक बाजारों से होने वाले मांग में भी भारी कमी आई है। इन बाजारों में खासकर यूरोप और उत्तर अमेरिका के बाजारों में मांग में भारी कमी आई है। इसके साथ ही अफ्रीकी महाद्वीप की आयात आपूर्ति में भी बाधा आई है विशेष रूप से औद्योगिक मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग व परिवहन उपकरणों के क्षेत्र में यह भारी कमी देखी जा रही है। क्योंकि उत्पादन के लिए आवश्यक आपूर्ति में भारी कमी है तथा तैयार माल की भी बाजार में मांग में कमी आ रही है इसके चलते कारखाने इस बात के लिए मजबूर हैं कि या तो वे अपना कामकाज बंद कर दें या फिर अपनी न्यूनतम क्षमता पर काम करें। अफ्रीका के भीतर देशों में आपसी व्यापार 16.7 प्रतिशत है जो कि इन उत्पादन के लिए पर्याप्त बाजार नहीं उपलब्ध करवा सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे देश लॉकडाउन कर चुके हैं इसलिए मैंनुफैक्चरिंग सेक्टर में फिलहाल निकट भविष्य में कोई सकारात्मक तस्वीर नहीं दिखती। हालांकि 2005 से 2014 के बीच (साइन, 2018) के अनुसार सेक्टर की औसत सालाना विकास दर 3.5 प्रतिशत थी और जीडीपी में इसका योगदान लगभग 10.9 प्रतिशत था। इसके अलावा और निराशा का माहौल भी है क्योंकि कार्यबल में से 11 प्रतिशत लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। इस बीच हाल ही में पूर्ण हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (एएफसीटीए) यह उम्मीद जगाता है कि 2030 तक उपभोक्ताओं का व्यय 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएगा। अफ्रीकी महाद्वीप में मांग में वृद्धि के साथ यहां की 1.2 बिलियन जनसंख्या तक आसान पहुंच तथा 2.5 ट्रिलियन डॉलर का समग्र जीडीपी अपने आप में इस बात की प्रेरणा देगा कि उत्पादन के स्तर को व्यापक बनाया जाए जिससे कीमतों में कमी आएगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

कोविड–19 और अफ्रीका की डिजिटल अर्थव्यवस्था

कोविड–19 के मद्देनजर, डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं, जो आमतौर पर वांछनीय हैं, ने अफ्रीका में और भी अधिक प्रासंगिकता प्राप्त की। डब्ल्यूएचओ ने वायरस के प्रसार को रोकने के साधन के रूप में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित किया। इस संबंध में, मोबाइल भुगतान प्रणाली एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपकरण बन गई है। मोबाइल राशि खाते ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, अफ्रीका में 60 प्रतिशत वयस्कों के पास ऐसे खाते हैं।

इसके अलावा, दूरसंचार कंपनियों और वाणिज्यिक बैंकों ने संकट से पहले ही टेलीकॉम के साथ एक इंटरफेस बनाया जिसने मोबाइल मनी खाता धारकों को अपने बैंक खातों में धन का उपयोग करने में सक्षम बनाया। कोविड–19 के मद्देनजर, वाणिज्यिक बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। इस उपाय से महाद्वीप में विशेष रूप से सामाजिक दूरी बनाए रखने के दौरान कमजोर पहुंच वाले वाणिज्यिक बैंकों तक पहुँचने में तनाव, यात्रा और भीड़ में कमी आएगी। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों और

दूरसंचार कंपनियों के बीच एक इंटरफेस बनाया गया है जो ग्राहकों को अपने मोबाइल मनी के माध्यम से अपने खातों में धन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है । यह सबसे लोकप्रिय भुगतान प्रणाली है। यह देखते हुए कि अफ्रीका की अधिकांश ग्रामीण आबादी शहरी निवासियों के धन पर निर्भर है, लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद ग्रामीण निवासियों पर तनाव को कम करने के लिए धन के निर्बाध हस्तांतरण को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि उच्च डिजिटल क्रय शक्ति, ऑनलाइन स्टोरों के बीच 21 मिलियन ग्राहकों की आबादी की सेवा, 18 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। किराने का सामान और अन्य आवश्यकताओं की तलाश में बाजार में गति पैदा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

कोविड–19: शांति, संघर्ष व संघर्ष के उपरांत अफ्रीका

एक बहुत ही दुर्लभ कदम में, उत्तर–पश्चिम और दक्षिण–पश्चिम कैमरन में अलगाववादी समूहों ने इस क्षेत्र में कोविड–19 के प्रकोप के मद्देनजर एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की। यह संघर्ष विराम सशर्त,अस्थायी और प्रतीकात्मक प्रतीक होता है,हालांकि फिर भी यह स्वागतयोग्य है। इस प्रतीकवाद के पीछे पूरी तरह से टूटी हुई स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है। इसके अलावा, आबादी का बड़ा हिस्सा – ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग – पूरे महाद्वीप में भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में कुपोषण से ग्रस्त हैं। उनके पास अस्तित्व बचाने लायक संसाधन भी मुश्किल से उपलब्ध हैं। ये सभी कारक कोवडि19 की प्रतिक्रिया को संघर्ष ग्रस्त व संघर्ष के उपरांत वाले अफ्रीकी क्षेत्रों में और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।

बहुपक्षवाद के लिए कोविड–19 चुनौती: अफ्रीका में क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय (आरईसी)

मोटे तौर पर यह एक वैश्विक प्रवृत्ति है, लेकिन कोविड–19 के दौरान यह अफ्रीका में क्षेत्रवाद की ताकत का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। राष्ट्रीय मूल्यांकन पर आधारित कई देशों ने सीमावर्ती बिंदुओं को बंद करने या आने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को निलंबित करने के लिए एकतरफा कार्रवाई की, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आयातित मामलों को कम करने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील थीं। क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों को समन्वय करने के लिए दी गई शक्तियों का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। । हालांकि, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के लिए आर्थिक समुदाय (ईसीओडब्ल्यूएएस) –जो राजनीतिक गतिरोध से निपटने के लिए लोकप्रिय है– की प्रतिक्रिया अद्वितीय थी। ईसीओडब्ल्यूएएस ने तुरंत कोविड–19 से निपटने की तैयारियों के लिए एक बैठक बुलाई। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) ने राष्ट्रीय तत्परता का एक सहकर्मी–समीक्षा मूल्यांकन भी शुरू किया, लेकिन अन्य आरईसी की तरह, यह क्षेत्र में पहले से ही दर्ज मामलों की प्रतिक्रिया थी। यह महत्वपूर्ण है कि आरईसी अफ्रीका में सीमा पार संक्रमणों की घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करता है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के सीमा पार सुचारू प्रवाह की सुविधा भी देता है। इसके अलावा, आरईसी सहयोगात्मक अनुसंधान और सर्वोत्तम

प्रथाओं को साझा करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

अफ्रीका में कोविड–19 का मुकाबला: राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां

अफ्रीकी देशों ने संकट के आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। जिन नीतियों में ऋण पुनर्गठन, ऋण अनुपात में कमी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बेचे गए बांडों की खरीद की बात की गई है उनका उद्देश्य न केवल तरलता बढ़ाना है, बल्कि व्यापार में बने रहने के लिए कमजोर कंपनियों का समर्थन करना भी शामिल है। हालांकि, इन विस्तारवादी मौद्रिक नीतियों से कुल मांग में वृद्धि होगी, फिर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति कम से कम अल्पावधि में निरंतर बनी रहने की उम्मीद है। इससे उच्च मुद्रास्फीति का खतरा है। रवांडा जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने आधारभूत खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य विनियमन के साथ नीतियां बनाई हैं, वहीं अन्य देशों ने अभी भी इसे कम–आय वर्ग के कल्याण को जोखिम में डालते हुए बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया है।

इसके अलावा, अधिकांश अफ्रीकी देश अपेक्षाकृत छोटे भंडार रखते हैं। प्रमुख क्षेत्रों के रूप में – पर्यटन और आतिथ्य, कृषि, तेल और गैस, कोविड–19 महामारी, और घरेलू राजस्व संग्रह में कमी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं कई अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं कठिन समय का सामना कर रही हैं। रवांडा आईएमएफ से 109 मिलियन डॉलर की रैपिड क्रेडिट सुविधा के साथ पहले से ही अपनी शेष राशि की भुगतान जरूरतों को पूरा कर रहा है, और इसी तरह का भविष्य कई अन्य अफ्रीकी देशों का इंतजार कर रहा है। यह भी स्पष्ट है कि अफ्रीका ने अपने अमरीकी डालर 500 बिलियन (विश्व बैंक, 2018) ऋण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता खो दी है। ऐसे में कोविड–19 के उपरांत सभी प्रमुख उधारदाताओं से ऋण पुनर्गठन और ऋण माफी की आवश्यकता होगी।

भविष्य की राह

अफ्रीका में कोविड–19 ने चिकित्सा और सैन्य अधिकारियों, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, नागरिकों और कॉरपोरेट्स की प्रतिक्रियाओं को आकर्षित किया है, और अस्थायी रूप से राजनीतिक विभाजन को ठीक किया है। अभी तक इस वायरस का अंत नजर नहीं आ रहा है। इस कारण से अफ्रीकी महाद्वीप में आर्थिक प्रगति का बुरी तरहं से प्रभावित होना तय है। यहां तक कि कम आय वाले समूहों के लिए भी ये भयानक परिणाम हैं। इस महाद्वीप पर आपूर्ति बाधित हो गई है और मांग घट रही है जो मंदी के लिए एक आदर्श नुस्खा है। हालांकि, प्रतिक्रिया, लचीलापन और वसूली बढ़ाने के लिए, इस महाद्वीप को विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को स्पष्ट करना होगा और उम्मीद है कि उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निरंतर समर्थन प्राप्त होगा। कोविड–19 रिकवरी योजनाओं के समन्वय में अफ्रीकी संघ यानी एयू की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा, एयू की सीमा पार डिजिटल व्यापार पर जोर देने के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने और महाद्वीप को क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका है। भविष्य की महामारियों की तैयारी में, एयू को क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य वस्तुएं प्रदान करने और अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

संदर्भ

एडोब। 2020. *एडोब डिजिटल इकोनॉमी इंडेक्स।* सैन जोसरू डॉब।

जयराम, के।, आचा, एल।, अमंडला, ओ।, और यिंग, एस।रों। 2020, 02 अप्रैल। मैकिंसे एंड कंपनी। *मैकिन्से एंड कंपनी* से लिया गयाः https://www-mckinsey-com/ featured& insights / Middle&East&and&africa / tackling& covid&19&in&africa

साइने, एल। 2018. *अफ्रीका में विनिर्माण और औद्योगिकीकरण की क्षमतारू रुझान, अवसर और चुनौतियां।* न्यूयॉकः ब्रूकिंग्स।

सुब्बन, वी। 2020, मार्च 17। अफ्रीकापोर्टल। अफ्रीकापोर्टल से लिया गयाः https: // wwwA africaportal-org/ features/impact&covid& 19&african&trade/

अंकटाड. 2018, दिसंबर 10 – अंकटाड से पुनर्प्राप्तः https: // unctad-org/en/pages/PressReleaseA aspÛ\ OriginalVersionID ¾ 493

–डब्ल्यूएचओ। 2020, 10. मार्च डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ से लिया गयाः https://www-afro-who-int/news/ south&african&development&community& unites&tackle&covid&19

–डब्ल्यूएचओ। 2020, फरवरी 18. डब्ल्यूएचओ, अफ्रीका। डब्ल्यूएचओ, अफ्रीका से लिया गयाः https: // www-afro-who-int/sites/default/ files/ COVID&19%20situation%20reports/ COVID&19&Bulletin_18%20Feb-pdf

क्यूबा ने कोरोना वायरस से लड़ने में सहायता के लिए अपने डॉक्टरों को दक्षिण अफ्रीका भेजा

क्यूबा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दक्षिण अफ्रीका की मदद करने के लिए 200 से अधिक डॉक्टरों को वहां भेजने पर सहमत हो गया है। इन डॉक्टरों को दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न प्रांतों में तैनात किया जाएगा। क्यूबा अपनी चिकित्सा कूटनीति के साथ–साथ महामारी से लड़ने के लिए अपनी सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यही नहीं, पूरी दुनिया में सर्वाधिक 'डॉक्टर–जनसंख्या अनुपात' क्यूबा में ही है।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का मानना है कि देश में कोविड संक्रमण की कुल संख्या अगस्त में अपने चरम पर पहुंच सकती है। इसके साथ ही उन्होंने अत्यधिक आत्मविश्वास के खिलाफ आगाह किया है। दक्षिण अफ्रीका में हजारों स्वास्थ्य कर्मी देश की आबादी की कोविड जांच में जुटे हुए हैं।

दक्षिण अफ्रीका अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने में मदद हेतु अपने 26 अरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज के वित्तपोषण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता भी मांग रहा है। देश के निर्धनतम परिवारों की सहायता के लिए सरकार कल्याणकारी अनुदान सृजित करने की तैयारी में है क्योंकि लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं।

स्रोतः बीबीसी। (2020, 26 अप्रैल)। कोरोना वायरसः क्यूबा के डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका भेजे गए हैं। https:// www.bbc.com/news/world-africa-52431627 से हासिल।

कोविड–19: अफ्रीका के लिए अभूतपूर्व चुनौती

*महेश सी. अरोड़ा**

''अफ्रीका को इस बात का लाभ है कि वे दूसरे देशों , जिनमें चीन, अमेरिका व यूरोप शामिल हैं,के अनुभवों से सीख कर अपने यहां बड़ी संख्या में मौतें होने से रोक सकते हैं।''

कोविड–19 मूल रूप से हमारे समाजों पर गहरा हमला कर रहा है। 1.3 बिलियन की आबादी के साथ, अफ्रीका के अन्य महाद्वीपों की तुलना में कहीं अधिक पीड़ित होने की संभावना है। कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया, एचआईवी और तपेदिक की व्यापकता शहरी इलाकों में रहने वाली लगभग 40 प्रतिशत आबादी और भीड़–भाड़ वाली झुग्गियों में लगभग 53 मिलियन के साथ अपने बोझ को और अधिक बढ़ाने वाली है। उनमें से अस्सी प्रतिशत प्रतिदिन 5.50 अमरीकी डालर से कम पर रहते हैं, उनमें से लगभग 70 प्रतिशत 30 वर्ष से कम आयु के हैं और लगभग चार प्रतिशत 65 वर्ष से अधिक हैं। इसके तीन बच्चों में से पांच स्टंटिंग से पीड़ित हैं। उनमें से लगभग 40 प्रतिशत पानी के फैलाव वाले वातावरण में रहते हैं। उनकी स्वास्थ्य प्रणाली, जो पहले से बहुत अधिक खराब है, अभूतपूर्व चुनौती से प्रभावित होने वाली है।

16 मई 2020 तक, अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों में कोविड–19 से 2630 मौतों और 29454 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ 78194 मामलों के आंकड़े सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका (13524), मिस्र (11228), मोरक्को (6652) और अल्जीरिया (6629) से सबसे अधिक कोविड–19 के मामले सामने आए हैं। अफ्रीका CDC द्वारा किए गए प्रोजेक्ट–सिंडीकेट डॉट ओआरजी पर आर्किबी ओक्यूबे (आर2), की एक अत्यधिक चिंताजनक रिपोर्ट के अनुसार, इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अनुमान लगाया कि उप–सहारा अफ्रीका में 300,000 लोगों को इस वायरस के कारण जान गंवानी पड़ेगी। इसके अलावा इससे आर्थिक नुकसान भी होगा।

*निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), आरआईएस। ये व्यक्तिगत विचार हैं।

आईएमएफ के अनुसार, कोविड–19 2009 की तुलना में कहीं अधिक गहरी मंदी का कारण बना है। हमारे साथ अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के 51 कमजोर या संघर्ष प्रभावित देश हैं। इसने बेरोजगारी को ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा दिया है और चारों ओर वंचितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में दसियों हजार मौतें, अभूतपूर्व आर्थिक तबाही और लॉकडाउन अब आम बात हो गई है। इसने काम करने के संबंध में हमारी पुरानी मान्यताओं को बदल दिया है और हमारे कुछ उच्च लोकतांत्रिक समाजों को इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तानाशाही तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए मजबूर किया है।

अफ्रीका में इसके असहनीय प्रभाव से निपटने के लिए हमारी प्रतिक्रिया को अच्छी तरह से समन्वित किया जाना है। इस प्रतिक्रिया में वृद्धि किए बिना इसे त्वरित और निर्णायक, विज्ञान आधारित और सहकारिता आधारित बनाना है। जितना जबरदस्त इस बीमारी का प्रकोप है, प्रतिक्रिया भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। इससे निपटने के लिए बनी रणनीतियां स्थानीयकृत और विभेदित होनी चाहिएं। यह सब करते हुए यह मानकर चलना होगा कि इसके लिए कोई टीका या उपचार नहीं है और इसे केवल लोगों की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाकर तथा सामाजिक दूरी रखकर दबाया जा सकता है। उन्हें हाथ धोने के लिए चिकित्सीय सलाह का सख्ती से पालन करने की सलाह देनी होगी। अफ्रीका को इस बात का लाभ है कि वे दूसरे देशों –जिनमें चीन, अमेरिका व यूरोप शामिल है–के अनुभवों से सीख कर अपने यहां बड़ी संख्या में मौतें होने से रोक सकते हैं।

हालांकि इस महाद्वीप में सभी को इससे बहुत अधिक खतरा है, लेकिन जिन लोगों पर इसका तुरंत असर हो रहा है, उनमें महिलाएं, युवा, कम वेतन वाले श्रमिक, नए स्थापित एसएमई, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोग या असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जिनके पास बुनियादी सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा का अभाव है। इससे विशेष रूप से वे लोग प्रभावित होंगे जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं और आत्म–पृथक करने में असमर्थ हैं। इससे महिलाओं की गरीबी बढ़ेगी, उनके खिलाफ हिंसा बढ़ेगी और महिलाओं की समानता को गहरी चोट पहुंचेगी। अधिक से अधिक महिलाएं इसके बाद अवैतनिक कार्य कर रही होंगी। बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में और बड़े अनौपचारिक क्षेत्रों से जुड़े लोग इसके सबसे बड़े प्रभाव का सामना करने वाले हैं क्योंकि वे रोजाना कमाई कर अपने भोजन का इंतजाम करते हैं।

अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक होने के नाते, इस महाद्वीप में चीन के लगभग 10 मिलियन नागरिक हैं। हजारों अफ्रीकी छात्र चीन में अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी कोविड–19 से प्रभावित होने वाले हैं। वर्तमान अफ्रीकी विकास, जो काफी हद तक चीनी निवेश, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा संचालित है, भी तीव्रता से प्रभावित होगा। जारी व्यापार युद्धों और घटते निर्यात के कारण चीनी वित्तीय व्यवस्था के प्रभावित होने से इस क्षेत्र में आपातकालीन सहायता के लिए चीनी मदद सीमित होने की संभावना है। यूएनईसीए के अनुसार, अफ्रीकी विकास 3.2 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत तक गिरने की संभावना है और कमोडिटी की कीमतों में भारी गिरावट के साथ अफ्रीका अपने प्रमुख

क्षेत्रों जैसे खनन, पर्यटन, तेल और आतिथ्य में असहनीय वित्तीय दबाव का सामना करने के लिए बाध्य है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कोविड–19 की चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि पांच से 25 मिलियन नौकरियां जाएंगी जिससे 86 बिलियन से 3.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। आईएमएफ के पास उधार देने के लिए 600 से 700 बिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध हैं, लेकिन लगभग 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता होती है। इसने जी –20 से अपने संसाधनों को दोगुना करने के लिए कहा है ताकि गरीब देशों को ऋण राहत दी जा सके। कुछ मामलों में, पश्चिमी देशों ने अफ्रीकी देशों द्वारा ऋण की सेवा की अवधि को छह महीने तक बिना किसी रोक–टोक के स्थगित कर दिया है ताकि स्थानीय स्तर पर स्थिति से निपटने के लिए उन्हें चिकित्सा उपकरण खरीदने में सक्षम बनाया जा सके ताकि औद्योगिक जगत अफ्रीका में इस रोग की नई लहरों से प्रभावित न हो।

अफ्रीका सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का सामना करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोगों को काम पर वापस कैसे लाया जाए, छात्रों को स्कूलों में वापस कैसे लाया जाए और सामाजिक भेदभाव को कैसे कम किया जाए, जिसने दुनिया को अलग कर दिया है। कोविड–19 समस्या से बचाव के लिए भौतिक दूरियां, क्वारंटाइन, आईसोलेशन, लॉकडाउन, परीक्षण और तेजी से संपर्क स्क्रीनिंग के माध्यम से इसके संचरण को रोकना है। इस वायरस को दूर करने के लिए सेनीटाइजर्स या साफ पानी से लगातार हाथों को धोना भी आवश्यक है। इसी तरह, भोजन और सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोना भी आवश्यक है। दुर्भाग्य से, अधिकांश अफ्रीकी देशों में स्वच्छ बहने वाले पानी की कमी है, तथा आबादी काफी ज्यादा है। वहां परिवार में सभी साथ रहते हैं जिससे सामाजिक दूरी रखना संभव नहीं हो पाता है, जो वायरस को रोकने के लिए जरुरी है।

सामाजिक मिलन में भाग लेने वाले अफ्रीकी लोगों का प्रतिशत काफी ज्यादा है। जब तक कि उन्हें समाज की व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए ऐसे मुलाकातों से दूर रहने के लिए राजी नहीं किया जाता है, स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अफ्रीका को चिकित्सा उपकरण, कीटाणुनाशक, स्वच्छता उत्पाद, मास्क और वेंटिलेटर तथा उन्हें उपयोग करने के लिए बिजली और ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। चूंकि चिकित्सा कार्यबल में 70 फीसदी महिलाएं हैं, इसलिए वे सबसे ज्यादा जोखिम का सामना करने को बाध्य होती हैं।

अफ्रीकी देशों में वायरस से लड़ने की जिम्मेदारी अधिकतर सरकारों पर हैं। उनके यहां निजी सेक्टर यां विदेशी भागीदारों से ज्यादा मदद नहीं मिल रही है क्योंकि ये दोनों खुद ही वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच भी कुछ निजी संस्थानों के नेतृत्व, धार्मिक संस्थानों तथा प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों ने सरकारों को वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई है जो सराहनीय है। इसने निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा को धुंधला कर दिया है। विनिर्माण के पूरी तरहं बंद होने से प्रमुख सेक्टरों में भी ठहराव आ गया है। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारी वित्तीय दबाव में है।

भारत पूरे विश्व को एक परिवार की तरहं मानता है। इसी सोच के तहत वह धार्मिक,

वैचारिक व भौगोलिक सीमाओं की परवाह न करते हुए अपने अनुभव तथा अत्यावश्यक दवाओं को दुनिया के साथ साझा कर रहा है। वह इन दवाओं को उन देशों को भेज रहा है जिन्हें इनकी बहुत ज्यादा जरुरत है मसलन दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, युगांडा व अफ्रीका के कई अन्य देश। इसके अलावा इस चुनौती से निपटने में भारत अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, ब्राजील, आस्ट्रलिया तथा अपने पड़ोसी देशों, जिनमें नेपाल व भूटान भी शामिल है, की मदद कर रहा है। इसके चिकित्सा पेशेवर विकासशील देशों में साझेदार संस्थानों के साथ अपने अनुभवों को वेबिनार की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से साझा कर रहे हैं। आरआईएस में ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर ने पहले ही पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की मदद से चिकित्सा पेशेवरों और कार्मिकों के लिए तीन वेबिनार आयोजित किए हैं और जल्द ही चौथा वेबिनार भी आयोजित किया जाने वाला है।

इस मोड़ पर, डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यापार को जारी रखने, लोगों को पहले से कहीं अधिक जोड़ने और उन्हें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने भी लोगों को सही दिशा दिखाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से यह जानकारी लोगों तक पहुंची है कि कैसे इस स्थिति से निपटना है। दुर्भाग्य से, दुनिया भर में लगभग 3.6 बिलियन लोग ऑफलाइन हैं। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर और भारत ने इस संबंध में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग से काफी लाभ उठाया है। इस चुनौती से निपटने के प्रयासों में मुख्य सार्वजनिक नायक चिकित्सा पेशेवर हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स और सेनेटरी और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मदद मिल रही है, जो सार्वजनिक सुरक्षा दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए 24/7 काम कर रहे हैं।

मीडिया के उचित प्रबंधन के लिए फर्जी खबरों को तत्काल हटाना चाहिए। जनता की चिंताओं को प्रभावी ढंग से सामने लाने के लिए चिकित्सा, फिल्मों, नृत्य और दुनिया की प्रमुख हस्तियों द्वारा सोशल मीडिया और सभी टेलीविजन चैनलों पर व्यक्तिगत ऑडियो –वीडियो संदेशों की मदद ली जा सकती है। संगीत के क्षेत्र से, धार्मिक नेता और यहां तक कि कॉमेडियन, जिनमें आम जनता को राजनेताओं से अधिक भरोसा है, इन संदेशों को देकर मदद कर सकते हैं कि घर के अंदर रहना, सामाजिक और शारीरिक दूरी और लॉकडाउन का पालन क्यों आवश्यक है।

प्रमुख चुनौतियां हैं कि जीवन को कैसे बचाया जाए, आजीविका और मजबूत हो। चूंकि कोविड–19 के खिलाफ वैक्सीन 12–18 महीनों के बीच उपलब्ध होने की संभावना नहीं है या जब तक कि इसका अनुवांशिक अनुक्रम राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक एकमात्र संभव उपचार क्वारंटाइन और इसके पीड़ितों की प्रतिरक्षा में वृद्धि है। सुरक्षा के दिशानिर्देशों का पालन करके और श्रमिकों को आर्थिक सहायता देकर और घर से अधिक काम की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवसाय क्षेत्र को इस अशांत अवधि के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अफ्रीका को आयात, कच्चे माल के निर्यात पर अपनी बढ़ती निर्भरता को कम करना है और हल्के विनिर्माण क्षेत्रों के साथ–साथ कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष महत्व देकर खपत से अधिक आत्मनिर्भरता के लिए

जमीन पर उतरना है। उसे सूक्ष्म उद्यमियों का दृढ़ता से समर्थन करना है और व्यापक प्रभाव वाले उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना।

मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा प्रदाता अफ्रीका सहित दुनिया भर में अपने कारोबार में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं, और उन्हें उभरती स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आम जनता को अधिकतम संभव सहायता करनी चाहिए। इस पीड़ाजनक समय के दौरान, आम जनता के साथ जुड़ना इस चुनौती को पार करने का एकमात्र तरीका है।

कोविड–19 के कारण अफ्रीका में खाद्य संकट

कोविड–19 महामारी के कारण अफ्रीका में खाद्य असुरक्षा बढ़ी है । खाद्य आपूर्ति ठप होने से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। इसके अलावा, पूर्वी अफ्रीका में टिड्डों के झुंडों के कारण फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे महाद्वीप खाद्य आयात पर अधिक निर्भर हैं। दुनिया भर के देशों ने अपने खाद्य निर्यात को कम किया है जिससे अफ्रीकी देशों के सामने खाद्य संकट है।

लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण, खाद्य ट्रक छूटने के बावजूद काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके ड्राइवर अपनी सुरक्षा के लिए डरते हैं। एक ट्रकिंग लॉजिस्टिक्स फर्म कोबो360 ने कहा है कि नाइजीरिया, केन्या, टोगो, घाना और युगांडा में उसके बेड़े का लगभग 30 प्रतिशत काम नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के अनुसार, अफ्रीकी क्षेत्र के लाखों लोगों को व्यवधानों के कारण आवश्यक भोजन नहीं मिलने का खतरा है।

अफ्रीका में खाद्य फसलों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता, जिसमें भारत, वियतनाम और कंबोडिया शामिल हैं, ने अफ्रीकी देशों को अपने निर्यात को कम कर दिया है या प्रतिबंध लगा दिया है। इसी समय, भोजन की कमी के कारण अफ्रीकी देशों में खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि उप–सहारा अफ्रीका, जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयात क्षेत्र भी है, एक स्वास्थ्य संकट से सीधे खाद्य सुरक्षा संकट में जा सकता है।

नाइजीरिया के कृषि मंत्री नानोनो ने कहा है कि नाइजीरिया में सरकार द्वारा नियंत्रित रणनीतिक भंडार में कम से कम 38,000 टन अनाज है जिसे वह 100,000 अतिरिक्त टन के साथ फिर से भरने के बारे में सोच रहा है। उप–सहारा अफ्रीका के देश लगभग 40 प्रतिशत चावल के आयात पर निर्भर हैं। ये देश विशेष रूप से खाद्य संकट में फंसने के खतरे का सामना कर रहे हैं।

स्रोतः जॉर्ज एल. (2020, 27 अप्रैल). कोविड–19 इज एक्सेसब्रेंटिंग फूड शॉर्टेजिस इन अफ्रीका। विश्व आर्थिक मंच । https://thediplomat.com/2020/04/south-koreas-response-to- covid-19-in-africa /

कोविड–19 और नई भू–राजनीति

*प्रत्यूष शर्मा**

"यह कहा जा सकता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन के 'उत्तर' से 'दक्षिण' की ओर झुकने का जो सिलसिला पिछले कई दशकों से निरंतर जारी है, वह अब नई रफ्तार पकड़ेगा और इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हब (जो वर्तमान में चीन में है) का पुनर्वितरण आगे चलकर 'समूचे दक्षिण' में हो सकता है।"

पूरी दुनिया में किसी भी अन्य महामारी के मुकाबले बेहद ज्यादा कहर बरपाने के कारण 'कोविड–19 या कोरोना' का वर्णन करते समय तरह–तरह के शब्दों एवं उपमाओं का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, प्राकृतिक आपदा, दुर्लभतम, इत्यादि। जहां एक ओर लोगों का अपने पूरे जीवन में इससे पहले कभी भी सर्वत्र कहर ढाने वाली इस तरह की जानलेवा महामारी से वास्ता नहीं पड़ा था, वहीं दूसरी ओर जीवन के सभी पहलुओं यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण पर इसका जो व्यापक प्रभाव पड़ रहा है वह भी इससे पहले कभी देखा या सुना नहीं गया है। वैसे तो इसका प्रभाव सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में कमोबेश अत्यंत प्रतिकूल ही पड़ा है, लेकिन पर्यावरण का तो बिल्कुल सुखद कायापलट ही हो गया है। हालांकि, यहां तक कि पर्यावरण पर पड़े इस अनुकूल असर को भी अस्थायी या अल्पकालिक ही माना जा रहा है (हेनरिक्स, 2020)। उत्तर–दक्षिण की वैश्विक (विषमता) खाई न केवल वर्तमान परिदृश्य में और भी अधिक स्पष्ट नजर आने लगी है, बल्कि अब तो यह उत्तर और दक्षिण के सभी देशों में घरेलू स्तर पर भी साफ दिख रही है। बहुपक्षवाद और वैश्विक संस्थाएं जो मजबूत होने के बजाय पहले से ही कमजोर होती जा रही थीं, उन्हें अब 'वैश्विक उत्तर' में बड़ी तेजी से अपनाई जा रही संरक्षणवादी नीतियों और अहंकारी कदमों के कारण नए सिरे से विभिन्न खतरों एवं विश्वास की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस आलेख में 'उत्तर' एवं 'दक्षिण' के संबंधित क्षेत्रों पर पड़ रहे नोवल कोरोना वायरस के अलग–अलग प्रभावों और बहुपक्षवाद पर इसके स्पष्ट दबाव के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

* संयुक्त राष्ट्र के शांति विश्वविद्यालय, कोस्टा रिका में पीएचडी छात्र, संवाददाता, डीसीआर, व्यक्त किए गए विचार निजी हैं।

इस आलेख में मूल मुद्दों पर चर्चा करने से पहले 'उत्तर–दक्षिण' नामकरण के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। 'वैश्विक दक्षिण' क्या है और संबंधित 'उत्तर–दक्षिण खाई' क्या है, इसकी विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की जाती रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में 'दक्षिण' शब्द से आशय मुख्यतः दुनिया के उस हिस्से से था, जो एक समय यूरोपीय उपनिवेश था। इसने आगे चलकर औद्योगिक (उत्तर) बनाम गैर–औद्योगिक (दक्षिण) बहस–मुबाहिसा का रूप ले लिया और वर्तमान समय में 'वैश्विक दक्षिण' शब्द से तात्पर्य उस स्थान एवं लोगों से है जो समकालीन पूंजीवादी वैश्वीकरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं (महलर, 2017)। यह सौभाग्य की बात है कि 'वैश्विक दक्षिण' में कोविड–19 के पॉजिटिव मामलों और संबंधित मौतों की संख्या 'वैश्विक उत्तर' की तुलना में अत्यंत कम है। हालांकि, यदि महामारी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में बड़े पैमाने पर फैलती है, तो 'वैश्विक दक्षिण' में कोविड–19 के पॉजिटिव मामलों और संबंधित मौतों की संख्या बड़ी तेजी से 'वैश्विक उत्तर' की तुलना में बढ़ जाएगी। परीक्षण सुविधाओं, नैदानिक किट, अस्पताल, वेंटिलेटर, और स्वास्थ्य प्रोफेशनलों की संख्या अपेक्षा से काफी कम रहने के कारण इन देशों में स्थिति काफी बिगड़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में कोविड के कुल मरीजों की संख्या फिलहाल नियंत्रण में है। अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, मिस्र और मोरोक्को कोविड से सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। इन देशों में कोविड–19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 4000 से कम है और समस्त सब–सहारा अफ्रीकी देशों (कैमरून और घाना को छोड़कर) में कोविड–19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1000 से कम है। हालांकि, पूरे महाद्वीप में कोविड रोगियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है (वर्ल्डोमीटर्स, 2020)।

जब हम विभिन्न अफ्रीकी देशों में वेंटिलेटर और आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) बेड की कुल संख्या को ध्यान में रखते हैं, तो स्थिति बड़ी विकट नजर आती है। उदाहरण के लिए, दक्षिण सूडान में 12 मिलियन की आबादी के लिए महज 24 आईसीयू बेड ही हैं (स्मिथ, 2020)। इसी तरह 15 मिलियन की आबादी वाले सोमालिया में प्रति मिलियन आबादी के लिए केवल 1 आईसीयू बेड है। उधर, कई देशों में रहने वाले लोगों के लिए वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं के बराबर है। दक्षिण सूडान में 4, लाइबेरिया एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य में 3, और सिएरा लियोन में 13 वेंटिलेटर हैं। वहीं, दूसरी ओर इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में 172,000 वेंटिलेटर और 64,000 आईसीयू बेड हैं। कमोबेश यही स्थिति डॉक्टरों की संख्या के मामले में भी है। सिएरा लियोन में प्रति 10,000 लोगों पर 0.25 मेडिकल डॉक्टर हैं। यह संख्या ज्यादातर पश्चिम अफ्रीकी और सब–सहारा अफ्रीकी देशों में 1 से कम है। वहीं, दूसरी ओर सभी उत्तरी देशों में यह संख्या 20 से काफी अधिक है (डब्ल्यूएचओ, 2020)। इस मामले में लैटिन अमेरिका में स्थिति अफ्रीका और एशिया की तुलना में बेहतर है। ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देशों में डॉक्टरों की संख्या उत्तरी देशों के साथ तुलना करने योग्य है। यही कारण है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संबंधित देशों की प्रति मिलियन आबादी पर किए गए कोविड परीक्षण (टेस्टिंग) की कुल संख्या भी लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के अनुपात में है। यह आंकड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका में 13073, स्पेन में 19896, इटली में 25028 और जर्मनी में 24738 है। वहीं, दूसरी ओर अफ्रीका में सर्वाधिक कोविड मौतों वाले

देश अल्जीरिया (402) में एक मिलियन की आबादी पर केवल 148 परीक्षण किए जा रहे हैं। (वर्ल्डोमीटर्स, 2020)। यह आंकड़ा तकरीबन 200 मिलियन की आबादी वाले नाइजीरिया (अफ्रीका में सर्वाधिक आबादी) में 39 है। उधर, 100 मिलियन से भी अधिक की आबादी वाले इथियोपिया ने अब तक केवल 5000 कोविड परीक्षण ही किए हैं।

कुछ औद्योगिक देशों में भी अलग–अलग क्षेत्रों में कोविड से मौतों के आंकड़े काफी भिन्न (प्रजाति एवं जातीयता के आधार पर) हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्वीकरण के विजेताओं और परास्त होने वालों पर भी कोविड का कहर एकसमान नहीं है। शिकागो के हालिया आंकड़ों से पता चला है कि वैसे तो इस शहर की कुल आबादी का सिर्फ 30 प्रतिशत अफ्रीकी अमेरिकी हैं, लेकिन वहां कोविड–19 से मरने वालों में 69 प्रतिशत लोग अफ्रीकी अमेरिकी ही हैं। इसी तरह लुइसियाना, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 15000 के करीब पहुंच रही है, की कुल आबादी में अफ्रीकी अमेरिकियों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है, लेकिन वहां कोविड–19 से मरने वाले कुल लोगों में से 70 प्रतिशत से भी अधिक अफ्रीकी अमेरिकी ही हैं (गुप्ता, 2020)। इस आंकड़े का काफी बढ़ जाना निश्चित तौर पर तय है क्योंकि अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई कुल मौतों में से लगभग 35 प्रतिशत के लिए ही प्रजाति एवं जातीयता संबंधी जानकारियां वर्तमान में उपलब्ध हैं (जेएचयू, 2020)। यहां तक कि भारत जैसे विकासशील देश, जहां श्रम बल का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और जो दिहाड़ी कामगार हैं, में अनौपचारिक या अनधिकृत साक्ष्यों से पता चला है कि यही विशेष समूह सबसे अधिक प्रभावित हुआ है (शर्मा, 2020)। वैसे तो भारत में अभी तक मौतों का अलग–अलग डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन

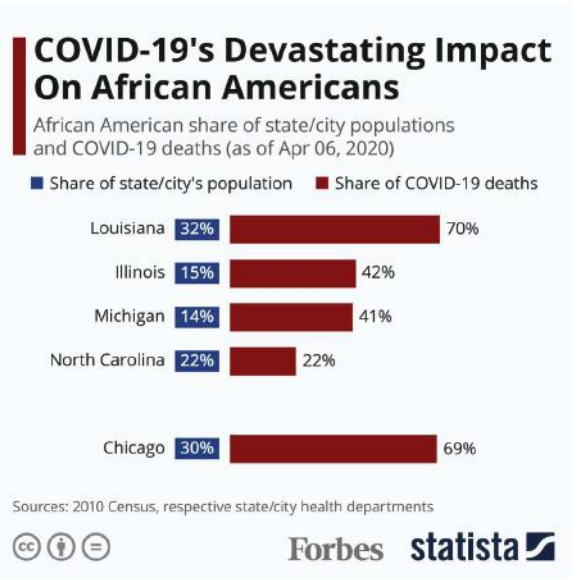

स्रोतः गुप्ता, 2020-

इस विशिष्ट समूह को लॉकडाउन से संबंधित नीतिगत अनिवार्यता के कारण जबर्दस्त आर्थिक झटके खाने पड़े और प्रवासन (माइग्रेशन) से जुड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 'उत्तर' और 'दक्षिण' के देशों के बीच डेटा की उपलब्धता में एकरूपता न होने के कारण ज्यादातर दक्षिणी देशों में अनौपचारिक या अनधिकृत साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सीमित डेटा होने एवं अंतर–अनुभागीय डेटा के अभाव के कारण दक्षिणी देशों के लिए समस्या की पहचान करना और समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त समय पर समुचित प्रासंगिक नीतिगत उपाय करना काफी कठिन हो जाता है।

यही नहीं, भू–राजनीति या वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी तेजी से बदलाव लाने में भी कोविड–19 का कोई जवाब नहीं है। राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी नाराजगी अक्सर दिखाई है, चाहे वह सुरक्षा क्षेत्र में नाटो गठबंधन के लिए हो (बोर्गर, 2019)

या संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विश्व व्यापार संगठन को नकारात्मक रूप से संदर्भित करना हो (जॉनसन, 2019)। राष्ट्रपति ट्रम्प ने यूएनजीए 74 में अपने कथित प्रसिद्ध भाषण में कहा, 'भविष्य वैश्विकतावादियों का नहीं है। भविष्य देशभक्तों का है' (गियरन और किम, 2019)। यहां तक कि महामारी के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को वित्तीय योगदान रोकने के बारे में की गई घोषणा से किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अमेरिका के कुछ सहयोगी देश जैसे कि जापान भी इसी तर्ज पर सोच रहा है (वाकात्सुकी, 2020)। इस बदलते हालात में यूरोपीय संघ (ईयू) में सहयोग और बहुपक्षवाद भी काफी खतरे में नजर आ रहे हैं। ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यह स्वीकार करते हुए यूरोप की ओर से इटली से 'हार्दिक माफी' मांगी कि आयोग इस संकट की शुरुआत से ही उसका साथ नहीं दे पा रहा था (गिल, 2020)। यही नहीं, अमेरिका और यूरोपीय संघ के आपसी संबंधों में भी तब खटास आ गई जब फ्रांस[1] और जर्मनी[2] ने अलग–अलग घटनाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका को मास्क की खेप को उस समय हाईजैक करने (अपने कब्जे में लेना) का दोषी ठहराया जब संबंधित शिपमेंट को क्रमशः शंघाई और बैंकॉक एयरपोर्ट से यूरोपीय देशों के लिए रवाना करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी।

इसके ठीक विपरीत महामारी के दौरान 'दक्षिण' में क्षेत्रीय सहयोग की विभिन्न पहल पूरी तरह से सफलतापूर्वक की जा रही हैं। 8 सदस्यीय दक्षिण एशियाई समूह 'सार्क' ने विशेष कोविड–19 आपातकालीन कोष के लिए 21.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित किए हैं (रॉश, 2020)। महाद्वीपीय स्तर पर द अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 'कोविड–19 परीक्षण में तेजी लाने के लिए साझेदारी (पैक्ट)' के तहत 1 मिलियन से भी अधिक कोविड–19 परीक्षण किट वितरित करने की योजना बनाई है, ताकि कोविड परीक्षण में कमी की समस्या को दूर करने में समूचे अफ्रीका के देशों की मदद की जा सके (अल जजीरा, 2020)। मध्य अमेरिकी देशों द्वारा एक क्षेत्रीय आकस्मिक योजना बनाई गई है (सिस्तेमा डे ला इंटेग्रैशन सेंट्रोअमेरिकेराना), जिससे कि न केवल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से, बल्कि इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों पर पड़ रहे व्यापक आर्थिक प्रभाव के नजरिए से भी वायरस के खतरे को नियंत्रित किया जा सके (सिका, 2020)। डॉक्टरों और हेल्थकेयर प्रोफेशनलों को दूसरे देशों में भेजने की परंपरा को निरंतर जारी रखते हुए क्यूबा मेडिकल ब्रिगेड ने 37 डॉक्टरों और 15 नर्सों को इटली भेजा (यह दक्षिण–उत्तर सहयोग का एक दुर्लभ अवसर है), ताकि वहां की ढहती स्वास्थ्य सुविधाओं को वापस पटरी पर लाने में आवश्यक सहयोग दिया जा सके (ऑन क्यूबा, 2020)। इसके अलावा, एक अभूतपूर्व वाकया यह हुआ कि वर्तमान में भारत में रह रहे लगभग 24000 अमेरिकी नागरिकों ने वापस अमेरिका नहीं जाने का फैसला किया, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने उन्हें स्वदेश वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था कर दी थी (टाइम्स ऑफ इंडिया, 2020)।

इन सबके मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन के 'उत्तर' से 'दक्षिण' की ओर झुकने का जो क्रम या सिलसिला पिछले कई दशकों से निरंतर जारी है, वह अब नई रफ्तार पकड़ेगा और इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण हब (जो वर्तमान में चीन में है) का पुनर्वितरण आगे चलकर 'समूचे दक्षिण' में हो सकता है। विभिन्न विशेषज्ञ पहले से ही संयुक्त राष्ट्र एवं डब्ल्यूएचओ जैसे

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन की मौजूदगी का विस्तार होने और प्रभाव बढ़ने का दावा कर रहे हैं (ली, 2020)। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे व्यापक प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 'उत्तर' वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चेन) पर नए सिरे से विचार कर सकता है और कुछ विनिर्माण यूनिटों को चीन से दूर स्थानांतरित कर सकता है, ताकि 'समूचे दक्षिण' में उत्पादन यूनिटों के वितरण या मौजूदगी के माध्यम से अपने जोखिमों में विविधता लाई जा सके। इसके साथ ही समस्त देशों को अब सचेत हो जाना चाहिए कि उन्हें वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं एवं वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकता को और भी अधिक गंभीरतापूर्वक पूरा करना होगा तथा अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने हेतु पूरी ईमानदारी से ठोस कदम उठाने होंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका (डेवी, 2020) एवं ग्रेट ब्रिटेन (नेविल, 2019) ने अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने के बजाय कम कर दिया है। वहीं, दूसरी ओर भारत ने हाल–फिलहाल में नहीं, बल्कि अभी से पांच साल बाद 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करने की योजना बनाई है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का महज 1 प्रतिशत है (सोनी, 2020)।

समाप्ति नोट

[1] द गार्जियन, 2020% https://www.theguardian.com/world/2020/ apr/02/global-battle-coronavirus- equipment-masks-tests

[2] ड्यूश वेले 2020% https://www.dw.com/en/berlin-accuses-us-of- hijacking-shipment-of-masks/av- 53017703

संदर्भ

अल जजीरा, 2020. ' अफ्रीका सीडीसी स्टेप्स अप कोरोना वायरस रेस्पॉन्स बाय रोलिंग आउट 1 मिलियन टेस्ट्स'. यहां उपलब्धः https://www.aljazeera.com/news/2020/04/africa-cdc-steps-coronavirus-response-rolling-1m-tests-200416142625589.html. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल (एक्सेस)।

बोर्गर, जे. 2019- *द गार्जियन* ट्रम्प रि–इलेक्शन कुड साउंड डेथ नेल फॉर नाटो, एलायज फियर , यहां उपलब्धः https://www.theguardian. com/world/2019/dec/02/nato-donald- trump-second-term. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल (एक्सेस)।

डेवी, एस. 2020, *द लांसेट* 'यूएस पब्लिक हेल्थ बजट कट्स इन द फेस ऑफ कोविड–19'. यहां उपलब्धः https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30182-1/ fulltext. 19 अप्रैल, 2020 को हासिल (एक्सेस)।

गिल, जे. 2020, *यूरोन्यूज* ''ईयू कमीशन प्रेसीडेंट ऑफर्स 'हार्टफेल्ट एपोलॉजी' टू इटली, एज एमईपी डिबेट कोरोना वायरस रेस्पॉन्स''. यहां उपलब्ध : https://www.euronews. com/2020/04/16/eu-commission- president-offers-heartfelt-apology-to-italy. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल।

गुप्ता, एस. 2020. *साइंस न्यूज* 'व्हाई अफ्रीकन–अमेरिकन्स मे बी एस्पेशियली वल्नरेबल टू कोविड–19' यहां उपलब्धः https://www.sciencenews.org/article/coronavirus- why- african-americans-vulnerable-covid- 19-health-race 15 अप्रैल, 2020 को हासिल।

गियरन, ए और किम, एस.एम. 2019- *वाशिंगटन पोस्ट* 'ट्रम्प कन्डेम्स ग्लोबलिज्म , टाउट्स नेशनलिस्टिक व्यू ऑफ फॉरेन अफेयर्स एट यू.एन.' यहां उपलब्धः https://www. washingtonpost.com/politics/trump- touts-nationalistic-view-of-foreign-affairs- at-un/2019/09/24/e4a8486a-ded2-11e9- 8fd3-d943b4ed57e0_story.html. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल।

हेनरिक्स, एम. 2020. *बीबीसी* 'विल कोविड–19 हैव ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एन्वॉयरनमेंट?'. यहां उपलब्धः https://www. b b c. com/future/article/20200326-covid- 19-the-impact-of-coronavirus-on-the- environment. 19 अप्रैल, 2020 को हासिल।

जॉनसन, के. 2019. *फॉरेन पॉलिसी* 'हाऊ ट्रम्प मे फाइनली किल द डब्ल्यूटीओ'. यहां उपलब्ध : https:// foreignpolicy.com/2019/12/09/ trump-may-kill-wto-finally-appellate- body-world-trade organization/. 17 अप्रैल, 2020 को हासिल।

जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी एंड मेडिसिन, 2020- रेसियल डेटा ट्रांसपैरेंसी। यहां उपलब्धः https:// coronavirus. jhu.edu/data/racial-data- transparency. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल।

ली, के. 2020- *पॉलिटिको* 'इट इज नॉट जस्ट द डब्ल्यूएचओ, चाइना इज मूविंग ऑन द होल यूएन'. यहां उपलब्धः https://www.politico.com/news/ magazine/2020/04/15/its-not-just-the- who-how-china-is-moving-on-the-whole- un-189029. 19 अप्रैल, 2020 को हासिल।

महलर, ए.जी. 2017. "ग्लोबल साउथ" *ऑक्सफोर्ड बिब्लियोग्राफीज इन लिटरेसी एंड क्रिटिकल थ्योरी* , एडिटर – यूजेन ओ' ब्रायन। न्यूयॉर्क : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

नेविल, एस. 2019- *फाइनेंशियल टाइम्स* 'फंडिंग कट्स टू प्रिवेंशन एंड केयर थ्रेटन एनएचएस विजन'. यहां उपलब्धः https://www.ft.com/ content/226a7c76-9104-11e9-b7ea-60e35ef678d2. 19 अप्रैल, 2020 को हासिल।

ऑन क्यूबा , 2020. 'द लाइफ दैट बिगिन्स फॉर क्यूबन डॉक्टर्स इन इटली'. यहां उपलब्धः https:// oncubanews.com/en/cuba/the-life- that-begins-for-cuban-doctors-in-italy/.18 अप्रैल, 2020 को हासिल।

रॉश, ई. 2020. *लाइव मिंट* 'पाकिस्तान प्लेजेज $3 मिलियन टू सार्क कोविड–19 एमरजेंसी फंड'. यहां उपलब्धः https://www.livemint. com/news/india/ pakistan-pledges- 3-mn-to-saarc-covid-19-emergency- fund-11586457666830.html. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल।

शर्मा, एन. 2020. *ब्लूमबर्ग क्विंट* 'फॉर वर्कर्स फ्लीइंग इंडियन सिटीज ऑन फुट, कोविड–19 इज द लीस्ट ऑफ देयर वरीज'. यहां उपलब्ध : https:// www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/for-workers- fleeing-indian-cities-on-foot-covid-19-is- the-least-of-their-worries. 19 अप्रैल, 2020 को हासिल।

सिका, 2020- 'सेंट्रल अमेरिका प्रेसीडेंट्स एलाय एगेन्स्ट कोविड–19' यहां उपलब्धः https://www.sica. int/noticias/central-america-presidents-ally-against- covid-19_1_121412.html. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल।

स्मिथ, ई. 2020. *डेवेक्स* 'दिज कंट्रीज हैव ओनली ए हैंडफुल ऑफ वेंटिलेटर्स'. यहां उपलब्धः https:// www.devex.com/news/ these-countries-have-only-a-handful-of- ventilators-96970. 16 अप्रैल, 2020 को हासिल।

सोनी, पी. 2020. *बिजनेस इंसाइडर* 'गवर्नमेंट इन्क्रीजेज हेल्थकेयर बजट बाय 10% –बट दैट मे नॉट बी सफिशिएंट'. यहां उपलब्धः https://www. businessinsider.in/budget/news/health-budget-2020-allocation- updates-and-news/articleshow/73830687. cms. 19 अप्रैल, 2020 को हासिल।

टाइम्स ऑफ इंडिया, 2020. 'ऐज 444 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फ्लाई होम, यूएस नेशनल्स प्रेफर टू स्टे.'. यहां उपलब्ध : https://timesofindia. indiatimes. com/india/as-444-from- australia-fly-home-us-nationals-prefer- to-stay-back/ articleshow/75113781.cms. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल।

वाकात्सुकी, वाई. 2020. *सीएनएन* 'शिंजो अबे सेज देयर आर इश्यूज विथ डब्ल्यूएचओ , एंड जापान विल रिव्यू इट्स फंडिंग आफ्टर द पैन्डेमिक'. यहां उपलब्धः https://edition.cnn.com/ world/live-news/coronavirus-pandemic- intl-04-17-20/ h_69ea3cf72279cba70faab19a cc7e912c. 18 अप्रैल, 2020 को हासिल।

डब्ल्यूएचओ, 2020. *'द ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी'* . यहां उपलब्धः https://www.who.int/ data/gho/data/ indicators/indicator- details/GHO/medical-doctors-(per-10- 000-population). 16 अप्रैल, 2020 को हासिल।

वर्ल्डोमीटर्स, 2020. यहां उपलब्धः https:// www. worldometers.info/coronavirus/. 23 अप्रैल, 2020 को 8:27 सीएसटी पर हासिल।

भारत–अफ्रीका संबंधः वर्तमान संकट और भविष्य

*अभिनव झा**

''महामारी से निपटने के प्रयास भविष्य की वैश्विक संरचना और उसका अंग बनने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में उभरते कथानक पर भी केंद्रित होने चाहिए।''

मौजूदा दौर में भारत और अफ्रीका के बीच के संबंध सबसे बेहतरीन अवस्था में हैं और इस समय वैश्विक महामारी ने हमें विभिन्न क्षेत्रों में तथा विविध तौर–तरीकों के माध्यम से इस महाद्वीप के साथ अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने का अवसर प्रदान किया है। इस वैश्विक महामारी के प्रकोप के दौरान एक–साथ काम करने से दोनों पक्षों को ग्लोबल पब्लिक गुड्स (जीपीजी) के प्रावधान के तहत दक्षिणीय सहयोग की ताकत प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। भारत और अफ्रीका के संबंध प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा अपनी यूगांडा यात्रा के दौरान निर्धारित किए गए सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। इन सिद्धांतों में कृषि में सुधार लाना, स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर निजी निवेश का प्रवाह बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, अफ्रीकी राष्ट्रों को डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए रूपांतरण (यानी डिजिटल–लेड ट्रांसमिशन्स) से लाभांवित होने में सहायता करना, अफ्रीकी नौजवानों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना तथा समावेशी विश्व व्यवस्था के लिए एकजुट होकर कार्य करने की दिशा में प्रयास करते हुए निरंतर साझेदारियों का निर्माण करना शामिल है। वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में भारत और अफ्रीका का मार्गदर्शन करने में इन सिद्धांतों का उपयोग संकटकाल में आपदाओं के प्रबंधन और उन पर काबू पाने के विकासशील देशों के सामर्थ्य की दुनियाभर में मिसाल पेश करेगा। दरअसल महामारी से निपटते समय भारत–अफ्रीकी साझेदारी को चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हैः

* पॉलिसी मैनेजर, जीडीसी। ये व्यक्तिगत विचार हैं।

स्वास्थ्य

यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि मौजूदा महामारी बुजुर्गों तथा मधुमेह, हृदयरोग आदि जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए जानलेवा है। इसलिए इस महामारी से निपटने का सबसे विश्वसनीय तरीका यही है कि बुजुर्गों और गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) से पीड़ित लोगों के लिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मौजूद हो। दुर्भाग्यवश अनेक विकासशील देशों में ऐसे बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, जिनमें एनसीडी से रोकथाम के बारे में जागरूकता की कमी है। मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अलावा, औषधियों की एक ऐसी विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला की भी जरूरत है, जो लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हो। वर्तमान में अनेक विकासशील देश एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडीअन्ट्स (एपीआई) के एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भर हैं और ग्लोबल वेल्यू चेन्स (जीवीसी) पर यह निर्भरता उन्हें काफी महंगी पड़ी है। मौजूदा संकट से संबंधित तीसरा पहलु वायरस में त्वरित गति से हो रहे जेनेटिक परिवर्तन हैं। इस त्वरित परिवर्तन से निपटना और होस्ट के जेनेटिक प्रोफाइल के उपयुक्त वैक्सीन तैयार करना ऐसी चुनौतियां हैं, जिनके लिए अत्याधुनिक जैव–प्रौद्योगिकीय कौशलों की आवश्यकता; है। उपरोक्त सभी बिंदुओं अर्थात बुजुर्गों और एनसीडी से पीड़ित लोगों के लिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता एपीआई आपूर्ति श्रृंखला के लिए जोखिमों को कम करना तथा विश्वसनीय फार्मास्यूटिकल वेल्यू चेन्स तैयार करना; तथा घरेलू जैव–प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का सृजन करना ऐसे क्षेत्र हैं, जो इस महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत–अफ्रीकी प्रयासों का केंद्र बिंदु हो सकते हैं। इसके तौर तरीकों में उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करना, केंद्रित निवेश निधियों का सृजन, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, सहयोगपूर्ण अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों की समस्याओं को कारगर ढंग से दूर करने में सक्षम अन्य कदम शामिल हैं।

कृषि

लॉकडाउन लागू करना महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने से संबंधित रोकथाम के उपायों में शामिल था। लॉकडाउन लागू करने वाले सभी देशों की घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को इसके कारण गंभीर अवरोधों का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा असहाय गरीब आबादी रही, जिसे खाद्यान्नों की कमी, भूख, कुपोषण और इसी तरह की बेहिसाब समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात से निपटने के लिए मजबूत खाद्य सुरक्षा प्रणालियों, वितरण और भंडारण के बुनियादी सुविधाओं साथ ही साथ कृषि उपज और पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। ये समस्त क्षेत्र विकासशील देशों में गरीबों पर इस महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों में कमी लाने के प्रति लक्षित कृषि क्षेत्र में भारत–अफ्रीका साझेदारी के लिए उपयुक्त केंद्र बिंदु हैं। इस क्षेत्र के तौर–तरीकों में प्राइवेट सेक्टर आउटरीच, स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का सहयोगपूर्ण विकास, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और अन्य उपयुक्त कदमों को शामिल किए जाने की जरूरत है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियां (आईसीटी आधारित ई–गवर्नेंस सहित)

संकट के इस दौर में लोगों के सीधे सम्पर्क में आने में कमी लाने की जरूरत ने ऐसे कई कार्यों

को अंजाम देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को आवश्यक बना दिया है, जिन्हें संकटकाल से पहले व्यक्तिगत रूप से किया जाता था। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए खरीददारी करने, समाचार पत्र पढ़ने, क्लासरूम में मौजूद रहकर पढ़ाई करने, दोस्तों के साथ मेल–जोल रखने, सहकर्मियों से मुलाकात करने आदि जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों को संक्रमण के बहुत कम जोखिम सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए इस संकट से भी कारगर ढंग से निपटा जा सकता है।

इस समय कुछ ऐसे ऐप उपलब्ध हैं, जिन्हें इस महामारी से संक्रमित लोगों की पहचान, प्रबंधन और उनके बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए तैयार किया गया है। इनसे महामारी से निपटने के लिए निवारक और अन्य उपायों को लागू करने हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आवश्यक कार्यकलापों के संबंध में ईज ऑफ गर्वनेंस में मदद मिलती है। इसलिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां महामारी के प्रति लक्षित किसी भी तरह के भारत–अफ्रीकी प्रयासों का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। इसके लिए चेलैंज फंड्स यानी किसी खास उद्देश्य के लिए धन आवंटित करने, सार्वजनिक निजी पहल, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सहयोगपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुसंधान और क्षेत्र विशेष से संबंधित अन्य तौर–तरीके शामिल हैं।

विकास की पद्धतियां और नई संरचनाएं

अंततः यह महामारी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए भी व्यवधान है। यह समस्त प्रचलित जीवीसी के ध्वस्त होने का कारण साबित हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश भी वही हैं, जो पुरानी व्यवस्था में प्रचलित आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता थे। लेटिन अमेरिकी देशों जैसे प्रमुख इनपुट आपूर्तिकर्ताओं, चीन जैसे विनिर्माण केंद्रों, ब्रिटेन जैसे वित्तीय केंद्रों और प्रमुख खपत केंद्रों जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ में निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में कमी आने का अनुमान है। ऐसे परिदृश्य में, जाहिर तौर पर व्यापार, निवेश, बौद्धिक सम्पदा और घरेलू सहायता को नियंत्रित करने वाली वैश्विक संधियों की अस्थायी तौर पर अनदेखी हो सकती है। इतना ही नहीं, नए स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता यानी सैनिटरी एंड फाइटो–सैनिटरी अवरोध भी शुरु किए जा सकते हैं, नई परीक्षण प्रक्रियाएं और मानक शुरु किए जा सकते हैं, लोगों की आवाजाही सीमित की जा सकती है तथा संभवतः वैश्विक स्तर पर नए नियमों और मानकों के बारे में विचार विमर्श किए जा सकते हैं। यह आवश्यक है कि यदि ये विचार–विमर्श हों तो उनका झुकाव किन्हीं खास देशों के प्रति न हो, बल्कि समावेशी हों और उनमें सभी पक्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। महामारी के संबंध में संक्रमणों और मौतों के संदर्भ में भारत और अफ्रीका अभी तक अपेक्षाकृत रूप से अनुकूल स्थिति में हैं हालांकि महामारी से निपटने के उनके प्रयासों में यदि भविष्य के आर्थिक घटनाक्रमों की अनदेखी की गई, तो यह अनुकूल परिस्थिति का रुख पलट सकता है। इसलिए महामारी से निपटने के प्रयास भविष्य की वैश्विक संरचना और उसका अंग बनने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में उभरते कथानक पर भी केंद्रित होने चाहिए। इसके तौर–तरीकों में गोल मेज सम्मेलन, विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय बैठकें, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं परामर्श तथा अन्य उपयुक्त उपाय शामिल हैं।

मौजूदा हालात में यह महामारी एक संकटपूर्ण स्थिति है। हालांकि देशों के बीच सहयोग से यह नवोन्मेषी परिवर्तनों का अवसर भी बन सकती है जो आगे चलकर ज्यादा समावेशी विश्व का रुख कर सकते हैं। भारत और अफ्रीका यदि इन क्षेत्रों में एक–दूसरे के साझेदार बन जाएं, तो वे केवल इस संकट से ही सफलतापूर्वक बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि विश्व के समक्ष जीपीजी के प्रावधान का एक शानदार उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे।

नवोन्मेशी प्रौद्योगिकी के साथ कोविड–19 से जंग लड़ रहा है दक्षिण अफ्रीका

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका में अप्रैल के आखिर तक लॉकडाउन रहा। ऐसे हालात में, इस महामारी के प्रकोप से निपटने में प्रौद्योगिकी बेहद उपयोगी साबित हुई।

कॉन्ट्रैक ट्रेसिंग ऐप्स दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं और अनेक देश अपने स्वदेशी वैरिएंट तैयार कर रहे हैं। यह ऐप संक्रमित लोगों को ट्रैक करने तथा पिछले 15 दिनों में उनके निकट सम्पर्क में आने वाले लोगों को जानकारी देने के लिए ब्ल्यूटूथ और लोकेशन टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी दूरसंचार कम्पनी टेलकॉम सैमसंग के साथ मिलकर सरकार को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में मदद कर रही है।

सैमसंग ने इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांतों को लगभग 1500 हैंड सेट्स वितरित किए हैं। टेलकॉम के फ्री मी पैकेज का उपयोग करने वाले ट्रैकर्स अगले 6 महीनों के लिए निशुल्क कनेक्टेड रहेंगे और वे देश भर में संक्रमित लोगों को ट्रैक एंड ट्रेस करने की सरकार की क्षमता को तीव्र गति प्रदान करेंगे।

हॉटस्पॉट्स की वास्तविक समय या रियल–टाइम पर परिकल्पना और पहचान करने में जीआईएस और लोकेशन टैक्नोलॉजीस विशेष तौर पर उपयोगी हैं। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने कम्युनिटी मैपिंग में शामिल निजी प्रौद्योगिकी कम्पनियों से भी सम्पर्क किया। उदाहरण के लिए, असुरक्षित समुदायों की पहचान और सहायता के लिए असुरक्षित समुदायों के मानचित्र में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया गया।

स्रोत : चतुर्वेदी, ए. (21,अप्रैल 2020)। हाओ साउथ अफ्रीका टैक टू फाइट कोविड–19। जियोस्पेटल वर्ल्ड https://www.geospatialworld.net/blogs/how-south-africa- uses-tech-to-fight-covid-19/ से उद्धृत।

कोविड–19 और अफ्रीका के सामने चुनौती

*आदिति गुप्ता**

''मौजूदा महामारी ज्यादातर अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में आय और रोजगार के स्तरों, खाद्य सुरक्षा की स्थिति, निर्यात राजस्व, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।''

परिचय

वैश्विक महामारी कोविड–19 ने जिस तरह समूचे विश्व को अपनी चपेट में रखा है, उसके कारण दुनियाभर के देशों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। देशों द्वारा अपनी सीमाएं बंद करने और लॉकडाउन लागू करने के कारण उनके समक्ष बढ़ती बेरोजगारी, सिकुड़ती उपभोक्ता मांग, घटते निर्यात, कम होते निवेश की आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्नत देश अपनी गरीब आबादी की सहायता के लिए आय हस्तांतरित करने और घरेलू संकट टालने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने जैसे कदम उठा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, ईरान, जर्मनी आदि जैसे देश मौजूदा महामारी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि महामारी के कारण 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 1 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है, जबकि इसके विपरीत पहले इसमें 2.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई थी। एक मूल्यांकन रिपोर्ट *''कोविड–19 एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क : इम्पैक्ट्स एंड रिस्पांसेज''* में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान व्यक्त किया है कि इस महामारी के कारण 2020 के अंत तक दुनिया में 25 मिलियन नौकरियां जा सकती हैं और कामगारों की आय में 860 बिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक की हानि हो सकती है।[1]

* अनुसंधान सहायक, आरआईएस। ये व्यक्तिगत विचार हैं।

कोविड–19 और अफ्रीका

अफ्रीकी देशों ने भी कोविड–19 के प्रभाव से निपटने के लिए कमर कसना शुरु कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, सेनेगल, सुडान, बुर्किना फासो आदि जैसे देश इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पहले ही लॉकडाउन लगा चुके हैं। सिएरा लियोन में 12 महीनों के लिए आपात स्थिति घोषित कर दी गई है, जबकि रवांडा ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। (रॉटबर्ग, 2020)

मौजूदा महामारी ज्यादातर अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में आय और रोजगार के स्तरों, खाद्य सुरक्षा की स्थिति, निर्यात राजस्व, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यूं तो शेष विश्व की तुलना में इस महामारी ने अफ्रीकी क्षेत्र में देर से दस्तक दी है, लेकिन यहां इसके कारण उत्पन्न चुनौतियों से सीधे तौर पर निपटने की जरूरत है।

सबसे निर्धन महाद्वीप होने के कारण यह महामारी अफ्रीका में कहर बरपा सकती है। अफ्रीकी देशों पर कोविड–19 के विविध प्रभावों को निम्नलिखित क्षेत्रों पर पड़े इसके प्रभाव के संदर्भ में समझा जा सकता है।

स्वास्थ्य: आबादी के जनसांख्यिकीय संदर्भ से विचार किया जाए, तो अफ्रीका की जनसंख्या अपेक्षाकृत युवा है। इसलिए शेष विश्व की तुलना में यह महाद्वीप बेहतर स्थिति में है, क्योंकि कोविड–19 के कारण होने वाली रुग्नता बुजुर्गों को ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, जैसा कि चीन या इटली जैसे देशों के मामले से सीखा जा सकता है। लेकिन अफ्रीकी देशों को अपने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मौजूद अनेक कमजोरियों के कारण इस विशाल संकट से निपटने में मुश्किल हो रही है। उदाहरण के लिए ज्यादातर अफ्रीकी देशों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का अभाव है साथ ही उनके पास प्रति व्यक्ति बिस्तर भी बेहद कम संख्या हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स सीमित हैं और वेंटिलेटर्स की कम सप्लाई आदि जैसे हालात बने हुए हैं। इसके अलावा, अफ्रीकी आबादी का एक बड़ा वर्ग मलेरिया, एचआईवी/एड्स, खून की कमी, कुपोषण आदि जैसी बीमारियों से जूझ रहा है, जो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर बनाती हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, क्षेत्र के लगभग 26 मिलियन लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं, जबकि 58 मिलियन से ज्यादा बच्चे कुपोषित और बौनेपन का शिकार हैं (कैलाघन एवं स्विलिंग, 2020)। ऐसी परिस्थितियों में, हो सकता है कि शेष विश्व की तुलना में अफ्रीका की युवा आबादी में कोविड–19 की कहीं समस्या ज्यादा गंभीर हो जाए।

तेल और अन्य जिंसें: वैश्विक व्यापार और यात्रा में रुकावटों के साथ ही चीन और अन्य देशों में तेल की खपत में कमी आने लगी, जिससे तेल की वैश्विक मांग में कमी आ गई। दुनिया भर में तेल के दाम गिरने से हालात और भी बिगड़ गए। ये सभी परिस्थितियां नाइजीरिया, घाना, लीबिया, अल्जीरिया आदि जैसे तेल उत्पादक और निर्यातक देशों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के अनुसार, तेल निर्यातक अफ्रीकी देशों को 65 बिलियन डॉलर तक के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है (स्मिथ, 2020)। तेल के अलावा, अन्य जिंसों के दाम गिरने से भी अनेक अफ्रीकी देशों के संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पडेगा। इसका कारण यह है कि इन जिंसों का निर्यात अनेक अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी का बहुत बड़ा अनुपात है। उदाहरण

के लिए, कांगो के लिए जिंसों का निर्यात उसके जीडीपी का 70 प्रतिशत भाग है तथा चीन को होने वाले निर्यात उसके कुल जीडीपी का 50 प्रतिशत है। इतना ही नहीं, विश्व के 70 प्रतिशत कोबाल्ट का उत्पादन अफ्रीका के इस कॉपर बेल्ट क्षेत्र में होता है और चीन विश्व में कोबाल्ट का सबसे बड़ा आयातक है (कैलाघन एवं स्विलिंग, 2020)।

कृषि: सीमाएं बंद होने, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में अवरोध ज्यादातर अफ्रीकी देशों में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। जिन देशों के कृषि उत्पाद उसके निर्यात का प्रमुख भाग हैं, उन्हें एशियाई देशों की ओर से कृषि उपज की मांग में कमी आने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एग्रीकल्चरल बिजनेस सेंटर के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका को लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की निर्यात हानि का सामना करना पड़ सकता है (उजु, 2020)। इतना ही नहीं, अफ्रीकी देशों को भंडारण की खराब सुविधाओं और खेतों के अल्प मशीनीकरण स्तरों का भी खामियाजा उठाना पड़ता है। लॉकडाउन और क्वारंटाइन के कारण श्रमिकों की संख्या में कमी हो जाने से ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता वाले फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण जैसे कार्य बाधित हुए। इन सभी कारणों से खाद्यान्नों के दामों में और ज्यादा वृद्धि और अनाज की कमी जैसे हालात उत्पन्न होंगे। घाना जैसे देशों में दहशत के कारण हो रही खरीददारी की वजह से पहले से ही बुनियादी खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ गए हैं।

आपूर्ति श्रृंखला: चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए अनेक अफ्रीकी देश इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू वस्तुओं, वस्त्रों आदि के लिए चीन के आयात पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका के लगभग 60 प्रतिशत परिधान और वस्त्र चीन से आयात किए जाते हैं (कैलाघन एवं स्विलिंग, 2020)। आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध के कारण प्रमुख अफ्रीकी देशों में अनेक छोटे और मझौले आकार के उद्यमों को अपना परिचालन बंद करना पड़ा है।

एयरलाइन : लॉकडाउन लगाए जाने और वैश्विक यात्रा बाधित होने के कारण दुनियाभर के एयरलाइन उद्योग को गंभीर नुकसान उठाने पड़े हैं। कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत होने के समय ही अफ्रीका के एयरलाइन उद्योग को राजस्व में लगभग 4.4 बिलियन डॉलर की हानि हुई थी। आईएटीए डेटा से पता चलता है कि 2020 में मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग्स में 20 प्रतिशत तक की कमी आई और घरेलू यात्रा में 15 प्रतिशत तक की कमी आ गई (कैलाघन एवं स्विलिंग, 2020)। एयरलाइन उद्योग के धराशायी हो जाने के कारण पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

तात्कालिक समाधान

इस बीमारी के कारण समूची दुनिया तथा अफ्रीका क्षेत्र में उपजे संकट पर गौर करते हुए घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के कुछ तात्कालिक उपायों में वित्तीय और मौद्रिक नीतियों का उपयोग किया जाना शामिल है। विभिन्न अफ्रीकी देशों की सरकारों को स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों पर अपना खर्च बढ़ाने तथा घरेलू मांग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

छोटे और मझौले कारोबारों को नकदी और कार्यशील पूंजी की कमी का सामना कर पड़ सकता है, ऐसे में उन्हें इस संकट से निपटने में सहायता देने के लिए आर्थिक राहत

पैकेज प्रदान करने की जरूरत है। अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर समस्त क्षेत्रीय संस्थाओं को खाद्य और अन्य आवश्यक आपूर्तियों का आवागमन सुनिश्चित करना चाहिए तथा आपूर्ति श्रृंखला के भीतर हो रही बर्बादी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए।

अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाए जाने की जरूरत है। जैसा कि अफ्रीकन इकॉनोमी आउटलुक, 2019 दर्शाता है कि यदि अन्य विकासशील देश अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को घटा कर आधा कर देते हैं,तो उस स्थिति में अफ्रीका हर साल अपने जीडीपी का 4.5 प्रतिशत अथवा हर साल 134 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी कर सकता है (मोंगा, 2020)।

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश और विश्व बैंक ने विश्व के निर्धनतम देशों को कर्ज में राहत प्रदान किए जाने का आह्वान किया है, ऐसे में कर्ज माफी अफ्रीकी क्षेत्र के लिए भी लाभदायक है। महाद्वीप का कुल विदेशी और घरेलू ऋण स्टॉक लगभग 500 बिलियन डॉलर है और मध्यम ऋण या मीडियन डेब्ट जीडीपी अनुपात में वृद्धि देखी गई है, जो 2008 के 38 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 54 प्रतिशत हो गई। इस तरह कर्ज माफी के बगैर अफ्रीकी देश प्रति व्यक्ति नकारात्मक वृद्धि की ओर धकेले जा सकते हैं। (मोंगा, 2020)।

कोविड–19 का प्रकोप गंभीर मानवीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है और अफ्रीकी देशों की राष्ट्रीय सरकारों के साथ विविध हितधारकों को इस संकट से एकजुट होकर निपटने की जरूरत है।

समाप्ति नोट

1 https://www.bloombergquint.com/global-economics/about-25-mn-jobs-could-be-lost-worldwide-due-to-coronavirus-un

संदर्भ

कैलन, एन एंड स्विलिंग, एम.2020,मार्च 27, कोवि. ड–19:इकॉनामिक इम्पैक्ट ऑन ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका। डेली मेवरिक https:// www-daily-maverick-co-za/article/2020& 03&27&cov-id&19&economic&impact&on&east& and&-southern&africa/

मोंगा, सी. 2020, मार्च 27, इकॉनामिक पालिसीस टू कॉम्बैट कोविड–19 इन अफ्रीका.प्रोजेक्ट सिंडिकेट।

https://www-project&syndicate- org/commentary/africa&four&ways&to& reduce&-covid19&economic&impact&by& celestin&monga&2020&03

रोटबर्ग आर.2020, अप्रैल 2। फॉर एन ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कॉन्टिनेन्ट, कोविड–19 इज एप्ट टू रीक हैवोक इन अफ्रीका। द ग्लोबल एंड मेलः ओपिनियन

https://www-theglobeandmail-com/ opinion/article&for&an&already&struggling& continent&covid&19&is&apt&to&wreak&havoc&in/

स्मिथ ई., मार्च19। एज द कोरोना वायरस एराइव्स इन अफ्रीका, फ्रेजाइल इकोनोमीज आर ब्रेसिंग फॉर द वर्स्ट। सीएनबीसी https:// www-cnbc-com/2020/03/19/as&the& coronavirus&arrives&in&africa&fragile& economies&are&bracing&for&the&worst-html

उजु, जे.। 2020, मार्च 29। पोटेन्शियल इम्पैक्ट ऑफ को. विड–19 ऑन अफ्रीकाज़ एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। दिसडःबिजनेस https:// www-thisdaylive-com/indeÛ- php/2020/03/29/potential&impact&of&covid&19&on&africas&agricultural&landscape/

विकास सहयोग की भाषा और स्वरूप

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता: वर्तमान महामारी से सबक

मिलिंदो चक्रबर्ती *

''हमने इस तथ्य को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि प्रकृति एक अद्वितीय जटिल प्रणाली के रूप में काम करती है जहां अनंत संख्या में प्राकृतिक प्रक्रियाएं आपस में एक–दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं।''

प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती है। इस मामले में प्रकृति का कोई जवाब नहीं है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा कहर ढाती है तो बार–बार यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। बाढ़ अथवा जंगल में लगी आग या चक्रवाती तूफान अथवा भूकंप इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि प्रकृति न केवल इंसानों के बीच, बल्कि मानव और अन्य जीवित प्राणियों के बीच भी कोई भेदभाव नहीं करती है। बाढ़ और जंगलों में लगी आग से बार–बार यह तथ्य उभर कर सामने आता रहा है कि किस तरह से इंसान और अन्य जंगली जानवर जीवित रहने के लिए लंबे समय तक आपस में साथ रहते आए हैं। याद करें वह अविस्मरणीय गाथा, किस तरह से नोह अपने परिवार को सैलाब से बचाने के लिए एक चाप या जहाज (आर्क) का निर्माण करता है।

हालांकि, जब भी प्रकृति एकदम शांत रहती है और किसी पर भी अपना रोष नहीं जताती है, तो वैसी परिस्थिति में आपसी होड़ ही विद्यमान संसार का मूलमंत्र रहती है। 'अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष में योग्यतम की जीत' का सिद्धांत आपसी होड़ के खेल का सामान्य नियम बन गया है। यही नहीं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के बीच एक–दूसरे से प्रतिद्वंद्विता के साथ–साथ एक ही सामाजिक वर्ग के लोगों के अंदर बढ़ती प्रतिद्वंद्विता आज के दौर का सामान्य चलन है। इस तरह की गैर वाजिब प्रतिस्पर्धी भावना तब और बढ़ जाती है जब कोई सामाजिक वर्ग सकुंचित दृष्टिकोण अपनाते हुए संसाधनों में कमी की विकट परिस्थितियों से अनुचित लाभ उठाना शुरू कर देता है। शिकारी इस प्रतिस्पर्धा में अपने शिकार पर हावी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रकृति यह सुनिश्चित कर देती है कि वंचित लोग अपने अस्तित्व को

* प्रबंध संपादक, डीसीआर और आरआईएस में विजिटिंग फेला

बनाए रखने के लिए बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ा लें। जाहिर है, कुछ विशेष प्रजातियों या वर्गों के बीच सह–जीवन एवं सह–अस्तित्व के अनेक उदाहरण हैं। वे अपवाद हैं।

मनुष्य और बाकी अन्य जीवित प्राणियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर इस तथ्य में निहित है कि जहां एक ओर अन्य जीवित प्राणी प्राकृतिक नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं, वहीं दूसरी ओर मानव ने एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना सीख लिया है जो आजीविका के लिए एक साधन के रूप में 'प्रकृति पर नियंत्रण' को अपरिहार्य मानता है। प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए आजीविका के साधन मानव की बढ़ती लालसा पूरी करने की दृष्टि से बेहद कम प्रतीत होते हैं। एक खास बात यह है कि हम प्रकृति के भौतिक और जैविक नियमों के बारे में अपनी गहरी समझ को व्यावहारिक रूप देकर कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति करने में सक्षम हो गए हैं। फिलहाल हमारी समझ से परे बाकी अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं की भी पुनरावृत्ति आज नहीं तो कल अवश्य कर लेने को लेकर हमारा दृढ़ भरोसा खुद ही हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार 'प्रकृति को नियंत्रित' कर सकते हैं।

हमने अपने आवागमन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की अवहेलना करने की सफल क्षमता हासिल कर ली है। चिकित्सा विज्ञान की बदौलत हम अब प्रकृति प्रदत्त अधिकतम जिंदगी से कहीं अधिक साल जीने में सक्षम हो गए हैं। ऐसे समय में जब प्रकृति की कृपा न हो रही हो, तब भी हम बादलों को सींच कर त्राहिमाम कर रहे क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करा सकने में सक्षम हो गए हैं। हम जल के प्राकृतिक प्रवाह को मोड़ कर इसे दूर–दराज के क्षेत्रों में ले जाने के लिए सिंचाई नहरों का निर्माण करते हैं। हमने लाखों वर्षों से जीवाश्मों में फंसी सौर ऊर्जा को बाहर निकालने की प्रौद्योगिकियां विकसित कर ली हैं। यही नहीं, हमारे द्वारा विकसित परमाणु क्षमता दुनिया के साथ–साथ प्रकृति को भी कई बार नष्ट करने में समर्थ है। प्राकृतिक वनों को काट कर इनके स्थान पर प्रायः वानिकी वृक्षारोपण किया गया और वहां की भूमि के अन्य संभावित उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया गया।

इन उपलब्धियों ने न केवल हमें आत्मसंतुष्ट एवं बेपरवाह कर दिया, बल्कि इस बात का भी पूरा भरोसा दिला दिया कि प्रतिस्पर्धा ही वह बुनियादी गतिशील ताकत है जिसके जरिए बड़ी तेजी से सामाजिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। 'प्रकृति पर नियंत्रण' ही दरअसल बाकी अन्य जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने की हमारी ताकत को तय करता है, जिनमें वे मनुष्य भी शामिल हैं, जो दुर्भाग्यवश प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल करने में पिछड़ जाते हैं। हम उन्हें 'विकसित' कहते हैं। हमने मानवता को दो विशिष्ट अलग–अलग समूहों में विभाजित कर दिया है। एक तरफ तो एक ऐसा समूह है जिसके पास नियंत्रण करने की क्षमताएं हैं, जबकि दूसरी तरफ वे बाकी अन्य लोग हैं जो प्रकृति पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए 'प्रथम' या 'विकसित' समूह से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं और इसके बदले में स्वेच्छा से या जबरन उसके द्वारा नियंत्रित होने के लिए भी तैयार हैं। जी हां, यही इस प्रतिस्पर्धा की कटु सच्चाई है।

प्रकृति को टुकड़ों–टुकड़ों में समझना

दुर्भाग्यवश, 'प्रकृति पर नियंत्रण' के लिए हमारी खोज टुकड़ों–टुकड़ों में हुई। हमने इस तथ्य को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि प्रकृति एक अद्वितीय जटिल प्रणाली के रूप में काम करती है जहां अनंत संख्या में प्राकृतिक प्रक्रियाएं आपस में एक–दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं। हम विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं की इस आपसी अंतर–निर्भरता को समझने या यहां तक कि अहसास करने में

भी अक्सर विफल रहे और प्राकृतिक नियमों से संबंधित अपने ज्ञान का उपयोग कुछ इस तरह से किया मानो कि इन प्रक्रियाओं को एक दूसरे से एकदम अलग करके शुरू किया जा सकता है। इसके अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। सिंचाई नहरों के निर्माण से पानी के प्राकृतिक प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी बाढ़ आती है। यह माना जाता है कि वनों की अंधाधुंध कटाई ही जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ने और यहां तक कि पशुजन्य (जूनोटिक) विषाणुओं के मानव में फैलने के लिए जिम्मेदार है। यह भी माना जाता है कि इबोला, सार्स, एमईआरएस और नोवल कोरोना वायरस से जुड़ी वर्तमान महामारी इसलिए काफी फैल गई है क्योंकि वायरस के स्ट्रेन पशुओं से निकल कर मानव शरीर में अपना डेरा जमा कर बड़ी तेजी से अपनी पुनरावृत्ति करने या प्रतिकृति बनाने में सक्षम हैं। इसी तरह हिमालय क्षेत्र में सड़कों के व्यापक नेटवर्क के निर्माण को ही बारंबार भूस्खलन के लिए अक्सर जिम्मेदार माना जाता है। उधर, नदियों पर पुलों के निर्माण को गाद के बड़ी मात्रा में जमा होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। वहीं, बांधों की वजह से जलीय प्रजातियों का अपने प्राकृतिक वास में आना–जाना करना और वहां रहकर अपना वंश बढ़ाना मुश्किलों भरा हो गया है।

'तुलनात्मक बढ़त' के बजाय 'प्रतिस्पर्धी बढ़त' : बढ़ती विषमता

प्रकृति पर अपना नियंत्रण बढ़ा लेने से मानव को अब प्रतिस्पर्धी व्यवस्था की शुरुआत करने का भरोसा हो गया। कई देश प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने में जुट गए। प्रत्येक राष्ट्र इस व्यवस्था की एक यूनिट के रूप में उभर कर सामने आ गया। कृत्रिम रूप से, यहां तक कि वर्षों से अक्षुण्ण रहने वाले प्राकृतिक परिदृश्य को भी दो भागों में विभाजित कर बनाई गई राष्ट्रीय सीमाओं को अब नई सामान्य स्थिति मान लिया गया। यही नहीं, हमने अपने पासपोर्ट से ही अपनी पहचान बना ली और होमो सेपियंस परिवार के एक सदस्य के रूप में प्रजाति स्तर की अपनी प्राथमिक पहचान गंवा दी। हमने राष्ट्रीय स्तर पर खुशहाली के कुल योग के रूप में वैश्विक स्तर पर खुशहाली को परिभाषित करने की ऐसी व्यवस्था तैयार की जिसमें राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को राष्ट्रीय कल्याण के स्तर को बढ़ाने में बिल्कुल उपयुक्त और प्रभावकारी माना गया। इतना ही नहीं, जीवन स्तर बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा को रामवाण मानते हुए राष्ट्र के भीतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की अवधारणा भी धीरे–धीरे जोर पकड़ने लगी। डेविड रिकार्डो ने अपनी प्रसिद्ध दलील में वैश्विक स्तर पर लाभ के लिए 'तुलनात्मक बढ़त' की वकालत की थी जिसे पलट कर 'प्रतिस्पर्धी बढ़त' को तवज्जो दी जाने लगी। 'तुलनात्मक बढ़त' में अपनी–अपनी सापेक्ष क्षमताओं के आधार पर विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का दोतरफा आदान–प्रदान करने की दलील दी गई। भले ही कोई देश प्रतिस्पर्धी बढ़त के साथ दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम हो, लेकिन यह वैश्विक कल्याण के हित में है कि संबंधित देश उस उत्पाद में माहिर बने जिसमें वह अपेक्षाकृत अधिक दक्ष है और वह दूसरे देश से उस उत्पाद को खरीदे जिसमें वह अपेक्षाकृत कम दक्ष है। इस दलील को दो देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के रूप में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर आदान–प्रदान के लिए मौजूदा समय में जिस 'प्रतिस्पर्धी बढ़त' पर विशेष जोर दिया जा रहा है उसमें सहयोग की भावना की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जिसकी वकालत रिकार्डो ने की थी।

'प्रतिस्पर्धी बढ़त' के पक्ष में दी गई दलीलों के कारण वैश्विक स्तर पर वृहद विभाजन हो गया। जिन देशों ने प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल कर ली, उन्होंने शक्तिशाली समूह का गठन कर लिया। वहीं, दूसरी ओर जो देश इसमें पिछड़ गए, उन्होंने शेष बचे देशों के समूह का

गठन किया। इसके अलावा, आय की सीढ़ी के शीर्ष पायदान पर रहने वाले चुनिंदा राष्ट्रों और इसके सबसे निचले पायदान पर रहने वाले ज्यादातर देशों के बीच की खाई निरंतर बढ़ती चली गई। यह समझने में कोई गलती न करें कि काफी हद तक 'प्रतिस्पर्धी बढ़त' का माहौल प्राकृतिक प्रणाली में अंतर्निहित जटिलताओं की पूरी तरह से उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप ही बना है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पारस्परिक निर्भरता वाले मानव–प्रकृति संबंधों को निरंतर बनाए रखने पर पड़ेगा।

मानव–प्रकृति की पारस्परिक निर्भरता: महत्वपूर्ण संतुलन को बनाए रखें

कोविड–19 महामारी का प्रकोप ठीक ऐसे समय में हुआ है जब हमने 'समावेशी विकास' पर गंभीरतापूर्वक विचार–विमर्श करना शुरू कर दिया है, जिसके सुनिश्चित होने पर कोई भी व्यक्ति विकास के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। यही नहीं, हमने निर्धारित समय सीमा में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) तक सफलतापूर्वक पहुंचने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। यह भी मानव जाति के इतिहास में एक बड़ी अच्छी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से मानवता को संभावित खतरों से जुड़ी चिंताओं को विभिन्न महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों पर बार–बार उठाया जा रहा है। ये दोनों ही चिंताएं मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों में नाजुक संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता की ओर इशारा कर रही हैं जिसके तहत प्रकृति के एक हिस्से के रूप में, न कि उसके नियंत्रक के रूप में मानव के अस्तित्व पर विशेष जोर दिया जाता है। ऐसे में हमारी राष्ट्रीय पहचान की सीमाओं को तोड़ते हुए होमो सेपियंस के रूप में हम सभी के बीच सहयोग बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा की भावना को ध्यान में रखकर हम जिन संकीर्ण राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में जुटे रहे हैं उन्हें काफी हद तक तिलांजलि देनी होगी, ताकि एक प्रजाति के रूप में हम अपने वजूद को निरंतर बनाए रख सकें।

कोविड–19 वायरस ने पूरी दुनिया में जो कहर ढाया है उससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। विश्व भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेने, इससे अभी तक प्रभावित न होने वाले देशों की संख्या के नगण्य होने और इससे मरने वालों की संख्या के 5 लाख से भी अधिक हो जाने के तथ्यों के मद्देनजर वैश्विक कल्याण के प्रतिस्पर्धा आधारित मॉडल के बजाय सहयोग आधारित मॉडल को अपनाने की आवश्यकता का अहसास करना अब कतई मुश्किल नहीं है। किसी भी बहस या विचार–विमर्श के बिना ही यह दलील स्पष्ट रूप से दी जा सकती है कि जिस सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में तत्काल वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है वह कोई और नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ही है। इस महामारी ने यह स्पष्ट रूप से दर्शा दिया है कि किसी भी व्यक्ति की रुग्णता एवं मौत से संबंधित प्रोफाइल दूसरों की तुलना में भिन्न नहीं है। वायरस जब फैलना शुरू करता है, तो वह दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय सीमाओं का कतई ख्याल नहीं रखता है। सर्वाधिक सख्त आव्रजन कानून भी इसे किसी भी देश में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं, चाहे वह प्रतिस्पर्धा के जरिए विश्व स्तर पर उभरने वाला कितना भी ताकतवर देश क्यों न हो।

स्वास्थ्य सेवाओं में वैश्विक सहयोग के पक्ष में

सही मायनों में वैश्विक सहयोग शुरू करने का सबसे आसान क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषकर संक्रामक रोगों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। किसी भी नई संक्रामक बीमारी का प्रकोप बढ़ने से अक्सर नई चुनौतियां उभर कर सामने आती हैं क्योंकि शुरू में इसकी कोई भी कारगर दवा नहीं होती है। जाहिर है, प्रकृति और नए वायरस के बीच की पारस्परिक निर्भरता

पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। दरअसल, चुनौती इनमें से कुछ आपसी जुड़ाव को समझने की है और इसके लिए वैश्विक स्तर पर ठोस प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं को इन दो कार्य–क्षेत्रों (डोमेन) में विभाजित किया जा सकता है – उपचारात्मक और निवारक। नैदानिक सेवाएं इन दोनों पुलों को आपस में पाटती या जोड़ती हैं। जब भी किसी नई बीमारी का प्रकोप होता है, तो नए रोगाणु के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है। इसकी जैविक और सूक्ष्मतम संरचनाएं कैसी हैं? यह किसी जीवित शरीर में कैसे प्रवेश करता है और फिर उस शरीर के अंदर बड़ी संख्या में अपनी प्रतिकृति कैसे बनाता है? इसकी प्रतिकृति बनाने की क्षमता को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? संक्रमित होने वाले रोगी की मृत्यु कदापि न होने देने के लिए कौन से औषधीय उपचार किए जा सकते हैं? इस रोग के मरीजों को कौन–कौन सी सहायक चिकित्सा सेवाएं दी जानी हैं? मौत होने के जोखिमों को कम करने के लिए इन सभी सवालों का उत्तर एक साथ दिया जाना जरूरी है। संक्रमित मरीजों को इस तरह की उपचारात्मक सेवाएं जल्द से जल्द मुहैया कराने में प्रभावकारी साबित होने के लिए पूरी दुनिया के विशेषज्ञों द्वारा सहयोग की भावना के साथ और चिर–परिचित प्रतिस्पर्धी सोच को तिलांजलि देते हुए ठोस प्रयास किया जाना नितांत आवश्यक है।

निवारक उपाय दो चरणों में किए जाते हैं। सबसे पहले, बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय किए जाते हैं। अतीत में संक्रामक रोगों से इस तरह से निपटने के अनुभवों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मानक प्रोटोकॉल अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं। अधिक समय गंवाए बिना ही रोग के विशिष्ट लक्षणों को जानने की उपयुक्त विधा विकसित की जा सकती है। दूसरा उपाय यह है कि एक ऐसा कारगर टीका (वैक्सीन) विकसित किया जाए जो रोगनिरोधी की भूमिका निभाए। दरअसल, यह टीका जब किसी व्यक्ति को लगाया जाएगा तो उसमें संबंधित रोगाणु के हमलों से रक्षा करने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तथा वैसी स्थिति में संक्रामक बीमारी को और अधिक फैलने से रोका जा सकेगा।

वैश्विक स्तर पर संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संगठनों के एक नेटवर्क के माध्यम से हो सकते हैं। यही नहीं, इसके लिए ऐसे सार्वजनिक और परोपकारी स्रोतों की ओर से वित्त पोषण हो सकता है जो इस तरह के अनुसंधान से तैयार होने वाली दवाओं, इत्यादि पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का दावा करने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। अतः यह संभवतः इन समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है। इस तरह के नेटवर्क के सदस्यों से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए, ताकि उभरते नए रोगाणुओं से भविष्य में होने वाले खतरों और संभावित उपचारात्मक उपायों की पहचान करना संभव हो सके। इनसे किसी और महामारी की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद मिलेगी। इस तरह के ज्ञान और उससे सृजित सेवाओं को वैश्विक स्तर पर सर्वसुलभ माना जाएगा जो किसी भी निजी लाभ के सृजन के दायरे से परे होगा। इन्हीं सिद्धांतों को नैदानिक किट के विकास के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

वर्तमान महामारी का प्रकोप बढ़ते ही हमें यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ कि बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने और संबंधित उपचारात्मक सेवाएं मुहैया कराने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा न केवल गरीब देशों, बल्कि कई धनी राष्ट्रों में भी निहायत ही अपर्याप्त है। यदि भविष्य में इस तरह की महामारी फिर से कहर ढाना शुरू करती है तो हम इससे लड़ने के लिए बेखबर होने या पूरी तरह से तैयार न होने का

जोखिम पुनः नहीं उठा सकते हैं। अतः स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक बुनियादी ढांचे में निवेश की एक बड़ी खुराक निश्चित तौर पर अपरिहार्य है। यहां पर यह बात दोहराना सही होगा कि महामारी का प्रकोप बड़ी तेजी से बार–बार नहीं होता है, इसलिए इसकी रोकथाम के उपायों पर किए जाने वाले निवेश पर अपेक्षा से कम रिटर्न मिलने की प्रबल संभावना है। अतः इस क्षेत्र में उन स्रोतों से निवेश नहीं आएगा जो तत्काल रिटर्न पाने में रुचि रखते हैं। सार्वजनिक निवेश के साथ–साथ सॉवरेन फंड और संभवतः पेंशन फंड को इस तरह की पहल में भारी–भरकम निवेश करना होगा।

एक निहायत ही अज्ञात रोगाणु या वायरस के फैलाव से उत्पन्न महामारी से एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई है। महामारी से लोगों की मौत होने के खतरे को कम–से–कम करने के लिए बड़े कदम उठाने की हमारी कवायद के तहत लाखों लोगों की आजीविका की सुरक्षा की अनदेखी कर दी गई है। सख्त लॉकडाउन लागू करने और 'सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपायों' के परिणामस्वरूप कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। आर्थिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं जिस वजह से वर्तमान उत्पादन स्तरों पर भारी नकारात्मक असर पड़ा है। यही नहीं, ये अर्थव्यवस्थाएं सामान्य स्थिति में कब वापस आएंगी, इसको लेकर व्यापक अनिश्चितताएं हैं। यहां तक कि इस पर भी संशय है कि हम वास्तव में नई सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण प्रायः निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विवश होने वाले मरीजों के उपचार की लागत काफी ज्यादा बैठ रही है। इस तरह की अनिश्चित स्थिति में वैश्विक समुदाय का एक बड़ा तबका वर्तमान संकट और भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आय संबंधी कुछ सहायता पाने की उम्मीद करेगा। एक खास बात यह है कि इस तरह की आय सहायता देने की मांग केवल कुछ चुनिंदा देशों में ही नहीं उठेगी, बल्कि यह एक वैश्विक आवश्यकता का रूप लेने जा रही है। भविष्य में महामारी का प्रकोप होने की स्थिति में उपयोग करने के लिए एक 'वैश्विक बुनियादी आय सहायता कोष' बनाना समय की मांग है। इस संसाधन का उपयोग अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी किया जा सकता है। प्रत्येक देश को इस कोष में योगदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह कोष आने वाले समय में सामान्य वर्षों के दौरान विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से और बढ़ जाएगा तथा इसका उपयोग केवल वैश्विक स्तर पर आपातकालीन हालात बनने पर ही किया जाएगा। इसी तरह विभिन्न देशों के क्षेत्रीय समूह भी अतिरिक्त सहायता कोष बना सकते हैं जिनका उपयोग केवल क्षेत्रीय स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी संकट गहराने के दौरान किया जाएगा। इस कोष में हर वर्ष जुड़ने वाली धनराशि का इस्तेमाल 'स्वास्थ्य से संबंधित एसडीजी3' की प्राप्ति के लिए कुछ अत्यंत आवश्यक कार्यों को पूरा करने में किया जा सकता है।

इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाएं सौहार्दपूर्वक ढंग से की जा सकती हैं, बशर्ते कि इस बारे में आम सहमति हो जाए। हालांकि, इसमें कोई शक नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मौजूदा व्यवस्थाओं में से कोई भी, चाहे वह बहुपक्षीय हो या द्विपक्षीय, इन जिम्मेदारियों को उठाने की स्थिति में नहीं है। अतः ऐसे में इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए बिल्कुल भिन्न प्रभावकारी नियम–कायदे बनाने और उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है।

योगदान देने वालों के लिए दिशा–निर्देश

1. डीसीआर एक संदर्भित बहु–विषयक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। पांडुलिपियों या हस्तलेखों को ईमेल–संलग्नक के रूप में एमएस–वर्ड में प्रबंध संपादक (milindo.chakrabarti@ris. org.in) को भेजा जा सकता है।
2. पांडुलिपियों या हस्तलेखों को डबल स्पेसिंग का उपयोग करके तैयार किया जाना चाहिए। पांडुलिपियों का मूल पाठ आमतौर पर 1500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। समकक्ष समीक्षा अनुभाग के लिए भेजी जाने वाली पांडुलिपियां 5000 शब्दों तक सीमित हो सकती हैं। इस तरह के प्रस्तुतिकरण में 200 शब्दों का सार और अधिकतम छह प्रमुख या सूचक शब्द होने चाहिए।
3. 'ise' , -isation' शब्दों में 's' का उपयोग करें; उदाहरण के लिए, 'civilise','organisation'। अमेरिकी वर्तनी के बजाय ब्रिटिश वर्तनी का उपयोग करें। अतः 'labor' के बजाय 'labour' लिखें। (2 percent, 3 km, 36 years old, इत्यादि)। सामान्य विवरण में 10 से नीचे की संख्या को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। thousands, millions, billions लिखें, न कि lakh और crore। संख्या और तारीख को संक्षेप के बजाय पूर्ण रूप में लिखें – उदाहरण के लिए 1980-88, pp.200-202 और pp.178-84 । उदाहरण के लिए 'the eighties', 'the twentieth century', इत्यादि।

संदर्भ शैली: संदर्भ को पेपर या आलेख के अंत में संलग्न किया जाना चाहिए। सभी संदर्भ निश्चित तौर पर डबल स्पेस में होने चाहिए, और यह होना चाहिए 'उसी लेखक को उद्धृत किया जाता है', इसके बाद प्रकाशन वर्ष के हिसाब से उन्हें कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें।

सभी संदर्भों को एपीए शैली में मूल पाठ में सन्निहित किया जाना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पाठ्यक्रम और विषय संदर्शिका या गाइड देखें:

https://pitt.libguides.com/c.php?g=12108&p=64730

हमारी मेलिंग सूची या लिस्ट में शामिल होने के लिए निमंत्रण

यदि पाठक 'डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू ' का सॉफ्ट वर्जन प्राप्त करने के लिए हमारी मेलिंग सूची या लिस्ट' में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो कृपया संगठनात्मक संबद्धता के साथ आरआईएस ईमेल पर: dgoffice@ris.org.in पर विवरण भेजें। यह भी निर्दिष्ट करें कि हार्ड कॉपी अपेक्षित है या नहीं।

योगदान के लिए निमंत्रण

हम सामान्य रूप से विकास सहयोग और विशेष रूप से दक्षिणीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर इच्छुक पाठकों से योगदान आमंत्रित करते हैं। आप अपने योगदान में विकास सहयोग से जुड़े सिद्धांत, व्यावहारिक कार्यकलापों और संबंधित बहस या वाद–विवाद को भी शामिल कर सकते हैं। नवीनतम प्रकाशनों जैसे कि पुस्तकों, मोनोग्राफ या विशेष लेखों, रिपोर्टों की समीक्षा भी स्वागत योग्य है। विकास सहयोग पर होने वाले किसी भी आगामी संस्थागत आयोजन को भी 'डीसीआर' में शामिल किया जा सकता है। योगदान 1500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

संपादकीय जानकारी, योगदान, प्रतिक्रिया या जानकारियों (फीडबैक) और टिप्पणियों के लिए milindo.chakrabarti@ris.org.in और dgoffice@ris.org.in पर मेल करें।

समकक्ष समीक्षा वाले लेखों/निबंधों पर एक अनुभाग या सेक्शन की शुरुआत

विभिन्न सुझावों, प्रतिक्रियाओं या जानकारियों (फीडबैक) और संचित अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सेक्शन शुरू करने का फैसला किया है जिसमें समकक्ष समीक्षा एवं पूर्ण लंबाई वाले लेख/निबंध सम्मिलित होंगे। योगदान करने के इच्छुक विद्वानों से अनुरोध है कि वे अपनी पांडुलिपियों (यदि संभव हो, तो 5000 शब्दों से अधिक नहीं) को संपादकीय कार्यालय में भेज दें।

'डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू' के बारे में

डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू (डीसीआर) का उद्देश्य वैश्विक विकास सहयोग से जुड़ी समग्र गाथा की बारीकियों को रेखांकित करना और दक्षिण यानी विकासशील देशों की अगुवाई वाली विकास सहयोग प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक निरूपण, अनुभवजन्य सत्यापन और प्रलेखन से जुड़ी अहम ज्ञान खाई को पाटना है। दक्षिणीय विकासशील देशों की दुनिया में विकास साझेदारियों की बढ़ती संख्या के बावजूद अब भी वैश्विक विकास प्रक्रियाओं में इसके योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी एवं विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। वैसे तो कुछ गतिविधियों या कार्यकलापों के दस्तावेजीकरण के लिए छिटपुट प्रयास होते रहे हैं, लेकिन दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) से जुड़े विविध अनुभवों को कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए सतत प्रयास अब भी नहीं किए जा रहे हैं। आरआईएस ने इस खाई को पाटने के लिए जीडीआई, एफआईडीसी और नेस्ट के साथ संयुक्त प्रकाशन में एक त्रैमासिक पत्रिका *'डीसीआर'* को लॉन्च करने का प्रयास किया है।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के बारे में

आरआईएस नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान है जिसकी परिकल्पना वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावकारी नीतिगत संवाद और क्षमता–निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट फोरम के रूप में की गई है। आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देने और विभिन्न फोरम में होने वाली बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों के साथ सहयोग करने पर फोकस किया जाता हैA @RIS_NewDelhi

वैश्विक विकास पहल (जीडीआई) के बारे में

आरआईएस में स्थापित वैश्विक विकास पहल (जीडीआई) का उद्देश्य भारत की विकास पहलों से संबंधित जानकारियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना और सिविल सोसायटी संगठनों सहित अपने संस्थागत साझेदारों की मदद से एशिया और अफ्रीका में विभिन्न जानकारियों को साझा करने के तहत उनकी प्रतिकृति या पुनरावृत्ति को बढ़ावा देना है। यह एक सूक्ष्म रूपरेखा के भीतर वैश्विक विकास प्रक्रियाओं का पता लगाने एवं उन्हें सुस्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही यह बहु–विषयक एवं बहु–व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित समानता, स्थिरता और समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में अन्य देशों की सीखने की प्रक्रियाओं की तुलना करने एवं अपनाने के लिए एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है।

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्सं (नेस्टं) के बारे में

दक्षिणी भागीदारों के बीच आंतरिक रूप से सृजित जानकारियों से विभिन्न वैश्विक नीति फोरम में ठोस आम मुद्दों को समग्र रूप देने में मदद मिल सकती है। दिल्ली में 'सदर्न प्रोवाइडर्स' के उच्च–स्तरीय सम्मेलन (मार्च 2013) में इन मुद्दों में से कई पर आम सहमति बन जाने और फिर यूएनडीसीएफ के अंतर्गत एसएससी पर कोर ग्रुप का गठन होने (जून 2013) के बाद 'नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्स (नेस्ट)' को 10–11 मार्च 2016 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 'दक्षिणीय सहयोग पर सम्मेलन' में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। 'नेस्ट' का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए एसएससी के दृष्टिकोणों पर विभिन्न जानकारियों को आपसी सहयोग से सृजित, व्यवस्थित, समेकित और साझा करने हेतु दक्षिणी (सदर्न) थिंक–टैंकों के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। @NeST_SSC

भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) के बारे में

एफआईडीसी का लक्ष्य दक्षिणीय सहयोग से जुड़े व्यापक रुझानों के विस्तृत विश्लेषण को प्रोत्साहित करना और सैद्धांतिक एवं अनुभवजन्य विश्लेषण, फील्ड वर्क, धारणा संबंधी सर्वेक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं के आधार पर हितधारकों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श को सुनिश्चित करके भारतीय नीतियों को प्रासंगिक बनाना है। @FIDC_NewDelhi

द्वारा प्रकाशित:

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, भारत । दूरभाष: 91-11-24682177-80
फैक्स: 91-11-24682173-74, ई-मेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: http://www.ris.org.in

Follow us on:

www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

वैश्विक दक्षिण में विभिन्न विकास सहयोग प्रक्रियाओं से सीखने और उन्हें साझा करने के प्रयासों के अंतर्गत जीडीआई द्वारा डीसीआर का प्रकाशन किया जा रहा है।

विषय वस्तु *(शेष सामने के कवर से जारी)*

भारत–अफ्रीका संबंधः वर्तमान संकट और भविष्य
अभिनव झा

कोविड–19 और अफ्रीका के सामने चुनौती
अदिति गुप्ता

परिप्रेक्ष्य

विकास सहयोग की भाषा और स्वरूप
स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में वैश्विक सहयोग की आवश्यकताः वर्तमान महामारी से सबक
मिलिन्दो चक्रवर्ती